नई दिल्ली
शनिवार
21 नवम्बर 2026
वर्षः 13, अंकः 78
पृष्ठः 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वैशाली में जनसभा की...पेज-05

DELHIN/2014/58158

वेलिंगटन टेस्ट दूसरा दिनः जायसवाल-राहुल ने भारत...पेज-06

एक नजर

दिल्ली बॉर्डर पर प्रदूषण के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का शिकंजा, 4,272 वाहन लौटाए

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बॉर्डर पर निगरानी तेज कर दी है। ग्रैप के तहत प्रतिबंधित श्रेणी के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए चलाए गए विशेष अभियान में पिछले 12 दिनों के दौरान 4,272 वाहनों को सीमा से ही वापस लौटा दिया गया। वहीं, नियमों का उल्लंघन करने वाले 246 वाहनों के चालान किए गए। नॉर्दर्न रेंज ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, 8 से 19 नवंबर के बीच नरेला और अमन विहार ट्रैफिक सर्कल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न बॉर्डर पॉइंट पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 41,986 गैर-निर्धारित वाहनों की जांच की गई। अभियान के तहत दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों के दस्तावेज और निर्धारित प्रदूषण संबंधी नियमों की जांच की गई। डीसीपी ट्रैफिक नॉर्दर्न रेंज डॉ. सचिन कुमार सिंघल के निर्देश पर विभिन्न बॉर्डर पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती की गई है। पुलिसकर्मी ग्रैप और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के दिशा-निर्देशों के अनुसार वाहनों की जांच कर रहे हैं। प्रतिबंधित श्रेणी में आने वाले वाहनों को नियमों के मुताबिक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को प्रभावी बनाने के लिए बॉर्डर पर जांच और सख्त की जाएगी। पुलिस का मुख्य उद्देश्य प्रतिबंधित वाहनों की राजधानी में एंट्री रोकना और दिल्ली की हवा को और प्रदूषित होने से बचाने में सहयोग करना है।

सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए श्रम एवं रोजगार क्षेत्र के साथ की चर्चा



नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को नई दिल्ली में रोजगार और श्रम क्षेत्र के हितधारकों के साथ महत्वपूर्ण प्री-बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। ये सीतारमण की आठवीं प्री-बजट बैठक थी। वित्त मंत्रालय ने 'एक्स' पर जारी पोस्ट में बताया कि यह आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले विभिन्न उद्योगों और समूहों से इनपुट एकत्र करने की सरकार की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बैठक की चर्चा का मुख्य रूप से इन महत्वपूर्ण क्षेत्र के प्रतिनिधियों की चिंताओं और सुझावों को संबोधित करने पर केंद्रित था। मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (वित्त मंत्रालय) के सचिव और श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2027-28 के संबंध में रोजगार और श्रम क्षेत्रों के हितधारकों के साथ आठवीं 'प्री-बजट परामर्श' बैठक की अध्यक्षता की। इस चर्चा का उद्देश्य आगामी केंद्रीय बजट के लिए रोजगार सृजन, कौशल विकास और श्रम सुधारों से जुड़े सुझाव एकत्र करना है।

वैश्विक शांति के लिए सांस्कृतिक जुड़ाव सबसे मजबूत गारंटीः मोदी

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के पहले 'सभ्यागत संवाद' में युद्ध और अशांति के बीच एकता एवं शांति का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि साम्राज्यों ने दुनिया के नक्शे बदले, लेकिन संस्कृति ने दुनिया के विचारों को बदलने और वैचारिक समृद्धि को ताकत देने का काम किया। हैं। संस्कृति हमें आपस में जोड़ती है और यही इस संवाद का मूल उद्देश्य है। यह एक नई परंपरा की शुरुआत है। प्रधानमंत्री ने पुराना किला में प्रथम शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सभ्यतागत संवाद मंच का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि साझा संस्कृति और सभ्यतागत विरासत ही विभिन्न देशों और समाजों को आपस में जोड़ती है और यह भारत की ही तरह विश्व में भी विविधता में एकता का आधार बन सकती है। उन्होंने भारतीय दर्शन के संदेश 'प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो' का उल्लेख करते हुए कहा कि सभ्यताओं के बीच संवाद का उद्देश्य भी आपसी सद्भाव, सहयोग और विश्व कल्याण की भावना को मजबूत करना है।



20 से 22 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस संवाद का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध और परस्पर जुड़ी सभ्यतागत विरासत को प्रदर्शित करना, लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना तथा अंतर-सांस्कृतिक संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री कहा कि आज जब दुनिया में युद्ध और अशांति के बीच शांति की उम्मीदों पर चर्चा हो रही है, तब शंघाई सहयोग संगठन के देश सभ्यताओं के जुड़ाव और संवाद पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह संवाद दुनिया को नई दिशा देने वाला मंच बन सकता है। उन्होंने कहा कि एससीओ देश संयुक्त प्रदर्शनियों, शोधकर्ताओं के आदान-प्रदान कार्यक्रमों और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके साथ ही साझा सांस्कृतिक मार्ग और विरासत परिपथ विकसित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने युवाओं को एक-दूसरे की भाषा, साहित्य और संस्कृति से जुड़ने के अधिक अवसर देने की जरूरत है। इसके लिए रचनात्मक मंचों के माध्यम से साझा विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है और स्थानीय कलाकारों को भी इन प्रयासों से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की तकनीक ने दुनिया में सांस्कृतिक जुड़ाव की नई संभावनाएं पैदा की हैं। एससीओ देशों को इन संभावनाओं का लाभ उठाना चाहिए। संग्रहालयों, पुस्तकालयों और अभिलेखागार में मौजूद अनमोल विरासत को तकनीक के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है।

प्राचीन ग्रंथों के डिजिटलीकरण और अनुवाद तथा संयुक्त शोध के जरिए नई जानकारियां सामने लाई जा सकती हैं। इससे एक देश में बैठकर दूसरे देश की सांस्कृतिक विरासत को बेहतर ढंग से समझना संभव होगा। प्रधानमंत्री ने भारत की ज्ञान विरासत और उसके दुनियाभर में हुए फैलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी शिक्षाएं जितनी प्राचीन हैं, उतनी ही सार्वभौमिक भी है। उद्घाटन समारोह में 'सभ्यताओं का संवाद - सांस्कृतिक प्रस्तुति' शीर्षक से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें संगीत, नृत्य, दृश्य कथावाचन और वर्णन का अनूठा समावेश रहा। 'वसुधैव कुटुम्बकम-विश्व एक परिवार है' विषय पर आधारित यह प्रस्तुति भारत और यूरेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करने वाली थी। इस फोरम पर भारत की पुरातात्विक, कलात्मक और साहित्यिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली 'अस्तित्व - हमारे अस्तित्व का सार' शीर्षक से प्रदर्शनियां भी आयोजित की गई हैं।

चिकित्सा क्षेत्र में नैतिकता, संवेदनशीलता और मानव सेवा को दें सर्वोच्च प्राथमिकताः राष्ट्रपति



नई दिल्ली,एजेंसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि युवा डॉक्टर पेशेवर नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करें और चिकित्सा सेवाओं में करुणा, संवेदनशीलता तथा मानवता की सेवा को सर्वोच्च स्थान दें। विज्ञान भवन में अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान (एबीवीआईएमएस) और डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने चिकित्सा शिक्षा में छात्राओं की उल्लेखनीय भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि बेटियों की उपलब्धियां चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं केवल शहरी और संपन्न आबादी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। राष्ट्रपति ने डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल की मरीजों को बेहतर सेवाएं देने में भूमिका की भी प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में अस्पताल की ओपीडी में 19 लाख से अधिक मरीज पहुंचे। इससे यहां पढ़ने वाले मेडिकल छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और क्लीनिकल ज्ञान हासिल करने का महत्वपूर्ण अवसर मिला।

मुर्मु ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक बदलाव आया है। सरकार के निरंतर प्रयासों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर उन्नत चिकित्सा सुविधाओं तक का विस्तार हुआ है। देशभर में करीब 1.75 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी चिकित्सा शिक्षा और सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को अपने घरों के नजदीक बेहतर इलाज मिलना संभव हुआ है। उन्होंने टेलीमेडिसिन को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से भौगोलिक दूरियों को कम कर दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों तक विशेषज्ञ चिकित्सा परामर्श पहुंचाया जा सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की स्वास्थ्य नीति अब केवल बीमारियों के इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि रोकथाम और समय रहते बीमारी की पहचान पर भी जोर दिया जा रहा है। मधुमेह, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और कैंसर जैसी गैर-संचारी बीमारियों की शुरुआती जांच और उपचार बेहद जरूरी है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर दिया जा रहा है। वहीं, आयुष्मान वय वंदना योजना के माध्यम से 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले में बंटे हुए फैसले पर अलग सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली,एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका को अलग से सूचीबद्ध करने की मांग को ठुकरा दिया जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाले मामलों को एक बड़ी पीठ के पास भेजने के फैसले को वापस लेने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि फैसले को वापस लेने की इस अर्जी और 'रेफरेंस ऑर्डर' के खिलाफ किसी भी चुनौती पर पांच जजों की संविधान पीठ ही विचार कर सकती है। यह संविधान पीठ पहले ही उन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए गठित की जा चुकी है, जिनमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' की वैधता को चुनौती दी गई है।



उच्चतम न्यायालय की दो जजों की पीठ ने 23 सितंबर को निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच जजों की बड़ी पीठ के पास भेजने के मुद्दे पर विभाजित फैसला सुनाया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अपने फैसले में कहा था कि मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की जरूरत नहीं है और इस पर दो जजों की पीठ ही फैसला कर सकती है। वहीं, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने मामले को संविधान पीठ के पास भेजने के पक्ष में फैसला दिया था।

संविधान केवल एक विधिक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि हमारे गणराज्य का नैतिक मार्गदर्शक हैः उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली,एजेंसी। उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बेनेट विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ द्वारा आयोजित 'संविधान सप्ताह समारोह 2026' के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे गणराज्य का नैतिक मार्गदर्शक है।



उन्होंने कहा कि संवैधानिक मूल्य केवल संस्थाओं और कानूनी ग्रंथों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उन्हें रोजमर्रा के सार्वजनिक जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी फलता-फूलता है, जब संस्थाएं जवाबदेह बनी रहें, असहमति का सम्मान किया जाए और नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कर्तव्यों को भी अधिकारों के समान महत्व दिया जाना चाहिए। उन?होंने कहा कि सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कर्तव्यों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन आवश्यक है। श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की लोकतंत्र संबंधी उस परिभाषा का स?मरण किया, जिसके अनुसार लोकतंत्र शासन का ऐसा स?वरूप है, जिसके माध्यम से लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन बिना रक्तपात के लाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां जनजीवन में हुए ठोस सुधारों के माध्यम से संवैधानिक आकांक्षाओं की पूर्ति को दर्शाती हैं। लगभग 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने, गरीबों के लिए चार करोड़ पक्के मकानों के निर्माण तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल की पहुंच 82 प्रतिशत से अधिक होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कभी विकास के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले सीमावर्ती गांव भी अब जीवंत गांवों के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियां प्रधानमंत्री श्री नरेन?द्र मोदी के नेतृत्व में संभव हुई एक मौन क्रांति को दर्शाती हैं। राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को उजागर करते हुए उपराष्ट्रपति ने संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के मूल्यवान योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि उनकी दूरदृष्टि को नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है।

रक्षा भूमि प्रबंधन में एआई और ड्रोन तकनीक का उपयोग समय की मांगः ओम बिरला



नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को कहा कि रक्षा भूमि प्रबंधन में एआई, जीआईएस और ड्रोन तकनीक का उपयोग समय की मांग है। बिरला यहां डिफेंस एस्टेट्स ऑर्गनाइजेशन (रक्षा संपदा संगठन) के सौ वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित 'डिफेंस एस्टेट्स सेंटेनरी लेक्चर 2026' को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर रक्षा भूमि के संरक्षण एवं सुव्यवस्थित प्रबंधन, राष्ट्रीय सुरक्षा और छावनियों में नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर विस्तार से चर्चा की गयी। बदलते समय की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए बिरला ने कहा, 'रक्षा भूमि प्रबंधन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए एआई, जीआईएस, ड्रोन तकनीक और डिजिटल रिकॉर्ड का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ई-छावनी, स्मार्ट, हरित और टिकाऊ छावनियों के निर्माण, पर्यावरण संरक्षण तथा ऐतिहासिक अभिलेखों को सहेजने जैसे प्रयासों को और गति देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अपनी समृद्ध विरासत, अनुभव और पेशेवर दक्षता के आधार पर रक्षा संपदा संगठन आने वाले समय में भी राष्ट्रीय सुरक्षा, सुशासन और जनकल्याण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा। इस मौके पर रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, सैन्य अधिकारियों और रक्षा संपदा प्रबंधन से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया और महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया।

खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली,एजेंसी। राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के बारे में कथित अपमानजनक बयान के मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज रूबी अलका गुप्ता ने 30 नवंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कुछ सवालों पर स्पष्टीकरण मांगा। जिसके बाद याचिकाकर्ता के वकील विजय कुमार ने समय देने का आग्रह किया। उसके बाद कोर्ट ने 30 नवंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया। इसके पहले 30 अक्टूबर को याचिकाकर्ता रविंद्र गुप्ता की ओर से वकील गगन गांधी और खरगे की ओर से प्रज्जवल सिंह ने लिखित दलीलें दाखिल की थीं। 28 सितंबर को मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने दलीलें



रखते हुए कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर कानून सम्मत फैसला किया है। इसके पहले 19 सितंबर को खरगे की ओर से इस बात से इनकार किया गया था कि वो लिखित वचन दें कि वो आरएसएस के खिलाफ कोई भी मानहानिकारक बयान नहीं देंगे।

याचिकाकर्ता रविंद्र गुप्ता ने कहा है कि वो आरएसएस का सदस्य होने के नाते याचिकाकर्ता मल्लिकार्जुन खरगे के बयानों से आहत है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खरगे पर एफआआईआर दर्ज करने की मांग की। इस मामले में तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था जिसके बाद याचिकाकर्ता रविंदर गुप्ता ने सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दरअसल, 13 दिसंबर 2024 को तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। मल्लिकार्जुन खरगे राज्यसभा के सांसद हैं इसलिए उनके खिलाफ अब राऊज एवेन्यू स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खरगे ने 27 अप्रैल, 2023 को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा और आरएसएस के बारे में अपमानजनक बयान दिए। याचिका में कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में कोर्ट ने सब्जी मंडी पुलिस थाने को एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। सब्जी मंडी थाने की पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बयान कर्नाटक में दिए गए हैं और वो सब्जी मंडी थाने के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

दिल्ली की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी परिवहन व्यवस्था, एनसीआर व पड़ोसी राज्यों से जुड़ रही कनेक्टिविटीः मुख्यमंत्री

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार



नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को आईएसबीटी कश्मीरी गेट से 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आनंद विहार आईएसबीटी से हापुड़ के बीच अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा की भी शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को केवल शहर की सीमाओं तक सीमित रखकर नहीं देखा जा सकता। एनसीआर और पड़ोसी राज्यों के अनेक शहरों से बड़ी संख्या में लोग रोजाना रोजगार, व्यापार, शिक्षा और अन्य कार्यों के लिए दिल्ली आते हैं।

सरकार का प्रयास है कि इन शहरों के बीच सार्वजनिक परिवहन की कनेक्टिविटी मजबूत हो, ताकि लोगों को निजी वाहनों पर निर्भर न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन के विकल्प बढ़ने से सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम होगा, यातायात जाम से राहत मिलेगी और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को भी गति मिलेगी। सरकार का लक्ष्य केवल बसों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसा आधुनिक सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क विकसित करना है, जो आम नागरिकों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सके। नई 100 इलेक्ट्रिक बसों में 50 बसें 9 मीटर और 50 बसें 12 मीटर लंबाई की हैं। सभी बसें वातानुकूलित, लो-फ्लोर वाली हैं। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए इनमें सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, रियल टाइम ट्रैकिंग और दिव्यांगजनों के अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इन बसों के शामिल होने के बाद दिल्ली का कुल बस बेड़ा बढ़कर 7,088 हो गया है। इसमें 5,338 इलेक्ट्रिक और 1,750 सीएनजी बसें शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने आनंद विहार आईएसबीटी और हापुड़ बस स्टेशन के बीच 12 इलेक्ट्रिक बसों की अंतरराज्यीय सेवा शुरू की है। यह सेवा दिल्ली, गाजियाबाद, पिलखुवा और हापुड़ के दैनिक यात्रियों को नियमित और किफायती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी। इस रूट पर दोनों दिशाओं में निर्धारित समय के दौरान हर 20 मिनट के अंतराल पर बसें संचालित होंगी। बसें गढ़ोली-उत्तर प्रदेश बॉर्डर, डाबर, मोहन नगर, न्यू और ओल्ड गाजियाबाद बस स्टैंड, हापुड़ चुंगी, आईएमएस कॉलेज (डासना), मसूरी, छिजारसी, कुलेच नगर, पिलखुवा और निजामपुर सहित प्रमुख स्थानों से होकर गुजरेंगी। इस रूट का किराया 124 रुपये निर्धारित किया गया है। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित, सुगम और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। 100 नई इलेक्ट्रिक बसों के जुड़ने से दिल्ली देश में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस बेड़ा रखने वाले शहर के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत कर रही है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2028-29 तक दिल्ली के बस बेड़े को लगभग 14,000 तक पहुंचाना है। दिल्ली से पानीपत और करनाल के लिए भी अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवाएं शुरू की गई हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार और पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी प्रदूषण कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। सरकार का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और भरोसेमंद परिवहन सुविधा उपलब्ध कराकर सार्वजनिक परिवहन को लोगों की पहली पसंद बनाना है।

रानी बाग के संत नगर में बनेगी 600 वाहनों की क्षमता वाली बहुस्तरीय पार्किंग, पीपीपी मॉडल पर होगा निर्माण

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) रानी बाग के संत नगर में करीब 3950 वर्गमीटर क्षेत्र में 600 वाहनों की क्षमता वाली बहुस्तरीय पार्किंग विकसित करने जा रहा है। इस परियोजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इससे पार्किंग निर्माण का खर्च निजी भागीदार वहन करेगा और निगम पर करीब 96.87 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि संत नगर में लंबे समय से बहुस्तरीय पार्किंग की मांग की जा रही थी। क्षेत्र में लगातार बढ़ते वाहनों के कारण पार्किंग की समस्या गंभीर होती जा रही है। बाजार में आने वाले लोगों और स्थानीय निवासियों को अपने वाहन खड़े करने में परेशानी होती है। इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था बेहतर होगी और सड़कों पर अवैध पार्किंग के कारण होने वाली यातायात संबंधी समस्याओं में भी कमी आएगी।

सत्या शर्मा ने कहा कि निगम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। मार्च 2024 में इस परियोजना को विभागीय स्तर पर करीब 96.87 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित करने की मंजूरी दी गई थी। अब इसे पीपीपी मॉडल पर आगे बढ़ाने की तैयारी की गई है, ताकि निजी भागीदारी से पार्किंग सुविधा विकसित हो सके और निगम के वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव न पड़े। योजना के तहत संत नगर, रानी बाग में लगभग 3950 वर्गमीटर जमीन पर बहुस्तरीय पार्किंग बनाई जाएगी। इसमें करीब 600 कार पार्किंग इकाइयों (ईसीएस) की क्षमता प्रस्तावित है। पार्किंग सुविधा विकसित होने से बाजार और आसपास के इलाकों में आने वाले लोगों को व्यवस्थित तरीके से वाहन खड़े करने की जगह मिलेगी। इससे सड़कों पर वाहनों की अवैध पार्किंग और यातायात जाम की समस्या कम करने में मदद मिलेगी। परियोजना को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के लिए निगम एक अनुभवी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) को परियोजना प्रबंधन सलाहकार एवं ट्रांजेक्शन एडवाइजर नियुक्त करेगा। सलाहकार परियोजना की तकनीकी और वित्तीय रूपरेखा तैयार करने, निविदा दस्तावेज बनाने, अनुबंध की शर्तें निर्धारित करने और निजी भागीदार के चयन की प्रक्रिया में निगम की मदद करेगा।

वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, तीन घंटे बाद पाया काबू



नई दिल्ली। दिल्ली स्थित वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार देर रात बर्तन बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग फैक्ट्री की पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल के अलावा छत तक फैल गई। छत पर टिन की चादरों का शेड बना हुआ था। आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दमकल विभाग के अनुसार गुरुवार देर रात करीब 10:03 बजे वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित ओल्ड स्टेट बैंक के पास एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी। इस दौरान कुल 18 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।फैक्ट्री में बेसमेंट के अलावा भूतल से तीसरी मंजिल तक निर्माण था। इसके ऊपर टिन शेड से ढकी छत थी। करीब 550 वर्ग गज क्षेत्र में बनी इस इमारत की पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल और छत पर आग फैल गई थी। दमकलकर्मियों ने अलग-अलग तरफ से आग बुझाने का अभियान चलाया। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात 01:30 बजे आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है।

लॉरेंस बिश्नोई के भाई के नाम पर मांगे 60 लाख, गिरफ्तार

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली स्थित जनकपुरी थाना पुलिस ने 60 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले को सुलझाते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित उत्तर प्रदेश के रायबरेली का आशु मौर्य (27) है। वह खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई बताकर कारोबारी के परिवार को वॉट्सऐप पर धमकी दे रहा था। डर पैदा करने के लिए उसने कारोबारी के घर रैपिडो राइडर के जरिए एक लिफाफा भी भिजवाया। इसमें लेमिनेट किया हुआ 10 रुपये का आधा नोट रखा था। पुलिस ने आरोपित के पास से चार मोबाइल टैबलेट, सिम कार्ड, मोटरसाइकिल और 10 रुपये के नोट का बचा हुआ आधा हिस्सा बरामद किया है।

पुलिस के मुताबिक, जनकपुरी निवासी जतिन गाबा ने शिकायत दी थी कि उनके परिवार को वॉट्सऐप पर धमकी भरे संदेश भेजकर 60 लाख रुपये की रंगदारी मांगी जा रही है। इसी दौरान उनके घर एक लिफाफा पहुंचा, जिसमें लेमिनेट किए गए 10 रुपये के नोट का आधा टुकड़ा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जनकपुरी थाने की टीम ने जांच शुरू की। पुलिस ने शिकायतकर्ता के घर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि लिफाफा पहुंचाने के लिए मानेसर से रैपिडो राइड बुक की गई थी। पुलिस ने रैपिडो राइडर पंकज गौतम से पूछताछ की। उसने बताया कि उसे संदिग्ध मोबाइल नंबर से ऑनलाइन बुकिंग मिली थी और मानेसर, गुरुग्राम से लिफाफा लेकर जनकपुरी में पहुंचाने को कहा गया था। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच के जरिए आरोपी के दूसरे मोबाइल नंबर का पता लगाया। यह नंबर रायबरेली निवासी आशु मौर्य के नाम पर रजिस्टर्ड मिला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने 60 लाख रुपये वसूलने की साजिश रची। आरोपित का पिता पिछले 27 साल से शिकायतकर्ता के यहां ड्राइवर की नौकरी कर रहा है। इस वजह से आरोपी कारोबारी और उसके परिवार को अच्छी तरह जानता था। उसे लगा कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल करने से परिवार डर जाएगा और रंगदारी की रकम देने को मजबूर हो जाएगा। पुलिस के अनुसार आरोपी ने 10 रुपये के नोट को लेमिनेट कराने के बाद उसके दो टुकड़े किए। एक हिस्सा लिफाफे में रखकर रैपिडो राइडर के जरिए कारोबारी के घर भिजवा दिया, जबकि दूसरा हिस्सा अपने पास रख लिया। इसके बाद उसने कारोबारी की पत्नी के मोबाइल पर वॉट्सऐप संदेश भेजकर खुद को अनमोल बिश्नोई बताया और 60 लाख रुपये की मांग की। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल मोबाइल और सिम कार्ड के अलावा तीन अन्य मोबाइल फोन, एक टैबलेट, नोट का दूसरा आधा हिस्सा और मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने धमकी देने के लिए किन तकनीकी माध्यमों का इस्तेमाल किया और इस साजिश में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं।

दिल्ली में 26 नवंबर को लगेगी डाक अदालत, 24 नवंबर तक भेजनी होगी शिकायत

नई दिल्ली। दिल्ली में डाक सेवाओं से जुड़ी लंबित शिकायतों के निपटारे के लिए 26 नवंबर को सर्किल स्तर की डाक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें केवल दिल्ली की मंडलीय स्तर की डाक अदालतों में उठाई गई उन शिकायतों पर विचार किया जाएगा, जिनका अब तक समाधान नहीं हुआ है। डाक विभाग के दिल्ली सर्किल के अनुसार डाक अदालत का आयोजन नई दिल्ली के झंडेवालान मेट्रो स्टेशन के पास मेघदूत भवन स्थित मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय की तीसरी मंजिल पर सुबह 11 बजे किया जाएगा। इसमें प्रत्येक शिकायतकर्ता की समस्या पर व्यक्तिगत रूप से विचार कर उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। डाक विभाग ने कहा कि शिकायतें सहायक निदेशक (सीएस), मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, दिल्ली सर्किल, नई दिल्ली 24 नवंबर तक भेजें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा। बजट घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट एक सप्ताह में पेश करने के निर्देश, पार्किंग, सामुदायिक भवनों और स्कूलों से जुड़े मुद्दों पर सख्ती।

लाल किले के पास फर्जी पार्किंग पर्ची काटकर वसूल रहा था रुपये, एक आरोपित गिरफ्तार



नई दिल्ली। दिल्ली स्थित लाल किले के पास दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के नाम पर फर्जी पार्किंग पर्चियां काटकर वाहन चालकों से रुपये वसूलने का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध पार्किंग का धंधा चला रहे मोहम्मद नौशाद (40) को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एमसीडी के नाम वाली पार्किंग पर्चियों की एक बुकलेट और 1300 रुपये नकद बरामद हुए हैं। बुकलेट में कुल 100 पर्चियां थीं। इनमें से 18 का इस्तेमाल किया जा चुका था, जबकि 82 पर्चियां खाली थीं। पुलिस के अनुसार 19 नवंबर को लाल किला पुलिस चौकी को सूचना मिली कि मेट्रो गेट नंबर-2 के पास अपर सुभाष मार्ग पर एक व्यक्ति एमसीडी के नाम से पार्किंग पर्चियां काटकर वाहन चालकों से पैसे वसूल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने एसआई सतीश के नेतृत्व में टीम बनाई। इसमें एसआई योगेंद्र कुमार और हेड कॉन्स्टेबल रोहित को शामिल किया गया। टीम ने सुबह 10:40 बजे मौके पर पहुंचकर निगरानी शुरू की। वहां एक व्यक्ति वाहन चालकों को पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के लिए आवाज लगा रहा था। पुलिस को देखकर उसने भागने की कोशिश की लेकिन टीम ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने उससे पार्किंग चलाने का लाइसेंस और एमसीडी की अनुमति के दस्तावेज मांगे लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। तलाशी के दौरान उसके पास से 1300 रुपये और एमसीडी ऑथराइज्ड एससीटी, बाइक पार्किंग के नाम से छपी पर्चियों की बुकलेट बरामद हुई। जांच में पता चला कि नौशाद को एमसीडी ने 17 दिसंबर 2024 से तीन साल के लिए पार्किंग चलाने का लाइसेंस दिया था। हालांकि, निर्धारित शुल्क और बकाया राशि जमा नहीं करने के कारण एमसीडी ने अगस्त 2026 में ही उसका लाइसेंस रद्द कर दिया था। इसके बावजूद वह पार्किंग चला रहा था और वाहन चालकों से पैसे वसूल रहा था। आरोपित के पास अब पार्किंग संचालन की कोई वैध अनुमति नहीं थी। इस मामले में कोतवाली थाने में 19 नवंबर को दर्ज प्राथमिकी के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह कब से अवैध रूप से पार्किंग चला रहा था और इस तरह कितने वाहन चालकों से रुपये वसूले गए। आरोपी मूल रूप से बिहार के सहरसा जिले का रहने वाला है। मामले की आगे जांच जारी है।

दिल्ली विवि दीक्षांत समारोहः पीयूष गोयल ने विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान का आह्वान किया



शबाना बेगम, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को यहां दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के स्नातकों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गोयल ने उनसे 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में योगदान देने का भी आह्वान किया। गोयल ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 103वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने अपने संबोधन में देश की आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पिछले एक दशक में लगभग 50 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। गोयल ने बताया कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभरा है। एक दशक पहले यहां कुछ सौ स्टार्टअप थे, जो अब बढ़कर 2,50,000 हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इनमें 130 से ज़्यादा यूनिकॉर्न शामिल हैं। गोयल ने स्नातकों के जीवन में उत्साह और उमंग की कामना करते हुए, उन्हें उनकी उपलब्धियों पर बधाई दी और उनके भविष्य के प्रयासों में सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युवा भारतीय अब नौकरी खोजने वालों के बजाय नौकरी देने वाले (जॉब क्रिएटर्स) बन रहे हैं। वे प्रयोग करने, असफलता को स्वीकार करने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के 104 साल के सफर का ज़िक्र करते हुए गोयल ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय 90 कॉलेजों और छह लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक बढ़ गई है और अपने 103 साल के इतिहास में कभी कोई कॉन्वोकेशन मिस नहीं किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने आजादी की लड़ाई, दूसरे विश्वयुद्ध और कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी परंपरा जारी रखी। उन्होंने कहा कि कॉन्वोकेशन में मौजूद होना उनके लिए डबल ऑनर की बात है, जहां 400 से ज़्यादा डॉक्टरेट डिग्री, 1.7 लाख से ज़्यादा बैचलर और मास्टर डिग्री और 160 से अधिक गोल्ड मेडल दिए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने स्नातकों को वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पहचानने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका अपना भविष्य उन लोगों से जुड़ा है, जिन्हें उनके समान अवसर नहीं मिल पाए हैं। उन्होंने छात्रों से कहा कि किसी एक व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने से मिलने वाली संतुष्टि का कोई मोल नहीं है।

महिला पहलवानों की याचिका पर बृजभूषण शरण सिंह ने जवाब दाखिल किया

नई दिल्ली। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बरी होने के खिलाफ दायर अपील पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने इस मामले में महिला पहलवानों की ओर से दलीलें सुनने के लिए 27-28 नवंबर की तारीख तय की है। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह की ओर से दलीलें सुनने के लिए 5 और 9 दिसंबर की तारीख तय की है।

कोर्ट ने महिला पहलवानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए 28 सितंबर को बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को नोटिस जारी किया था। चार महिला पहलवानों ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट के 3 अगस्त के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है। महिला पहलवानों ने कहा है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश गलत है और ये फैसला चुनिंदा साक्ष्यों के आधार पर दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी की है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 3 अगस्त को अपने आदेश में पीड़ित महिला पहलवानों की ओर से लंबे समय तक चुप करने और आरोपियों से सामान्य संबंध जारी रहने के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी करने का आदेश दिया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए थे। सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह की ओर से कहा गया था कि 7 सितंबर, 2022 को घटना वाले दिन वह भारत में नहीं थे। बृजभूषण के वकील राजीव मोहन ने कहा था कि ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस कमिश्नर को केंद्र सरकार ने भेजी थी। राजीव मोहन ने कहा था कि महिला पहलवानों का पहला विरोध प्रदर्शन 18 जनवरी, 2023 को जंतर-मंतर पर था। सुनवाई के दौरान महिला पहलवानों की ओर से वकील रेबेका जॉन ने कहा था कि ओवर साइट कमेटी नियमों के हिसाब से नहीं बनाई गई थी।

चांदनी चौक के कायाकल्प पर समीक्षा बैठक, सीएम रेखा गुप्ता ने दिए निर्देश

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली की मुख्यमंत्री एवं इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम (आईवीपीएन) की अध्यक्ष रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में पुरानी दिल्ली के कायाकल्प से जुड़ी एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों को समन्वित रूप से काम करने और क्षेत्र की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चांदनी चौक की ऐतिहासिक पहचान और गौरव को अक्षुण्ण रखते हुए बाजारों तथा रिहायशी इलाकों में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। बाजार में महिला शौचालयों का निर्माण, क्यूआर कोड आधारित शिकायत प्रणाली, बेहतर सफाई व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और अतिक्रमण हटाने जैसे कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया गया कि चांदनी चौक में 120 सफाई कर्मचारियों को तीन शिफ्टों में तैनात किया गया है, जिससे बाजार में 24 घंटे सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी इस व्यवस्था की पुष्टि की। आईवीपीएन अधिकारियों ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर काम शुरू हो चुका है। क्षेत्र की समस्याओं, तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले विषयों और दीर्घकालिक कायाकल्प योजनाओं का खाका भी प्रस्तुत किया गया।

मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम और पीडब्ल्यूडी को सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाने के लिए तत्काल समन्वित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फुटपाथों पर अनधिकृत कब्जे, सड़कों पर वाहनों का जमावड़ा और सार्वजनिक स्थानों का अवैध इस्तेमाल किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। व्यापारी प्रतिनिधियों ने भी अतिक्रमण हटाने, रिक्शों की संख्या नियंत्रित करने और अनधिकृत वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस और नगर निगम को संयुक्त रूप से अतिक्रमण रोकथाम टीम तैनात करने के निर्देश दिए। नगर निगम को रिक्शों की संख्या तत्काल प्रभाव से सीमित करने और उनके डिजाइन में सुधार पर ध्यान देने को कहा गया है ताकि यात्रियों और चालकों दोनों को बेहतर सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कश्मीरी गेट बस अड्डा (आईएसबीटी) के निकट फ्लाईओवर पर बसों के जमावड़े और वहां व्यावसायिक सामान की लोडिंग-अनलोडिंग होने पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने परिवहन विभाग को बुराड़ी स्थित आईएसबीटी को निर्धारित समय-सीमा में चालू करने के प्रयास तेज करने तथा इसके पूरी तरह संचालन में आने तक बसों को बुराड़ी आईएसबीटी परिसर में सरफेस पार्किंग की अनुमति देने के निर्देश दिए। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास से संचालित अवैध बसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाने को भी कहा गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर अनधिकृत पार्किंग और बसों के माध्यम से माल ढुलाई रोकने के लिए परिवहन विभाग के अंतर्गत दिल्ली पुलिस, यातायात पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों की संयुक्त प्रवर्तन टीम गठित कर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में नए महिला शौचालयों के निर्माण के साथ अन्य सार्वजनिक शौचालयों की संख्या बढ़ाने और उनकी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि पीडब्ल्यूडी के माध्यम से चांदनी चौक में सिविल रखरखाव, बागवानी, मशीनी सफाई और सुरक्षा सेवाओं को समाहित करते हुए व्यापक सुविधा प्रबंधन व्यवस्था विकसित की जा रही है। इसके अंतर्गत सड़कों और बुनियादी ढांचे की मरम्मत, नालियों एवं बोलार्ड का रखरखाव, गमलों और हरित गलियारों की देखभाल, 24 घंटे सफाई तथा गेट और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा जैसे कार्य किए जाएंगे। प्रस्तावित सिविल कार्यों का सर्वेक्षण और मैपिंग की जा रही है। बोलार्ड और बेंच ऑर्डर किए जा चुके हैं। खराब फर्श एवं टाइलों की मरम्मत और बदलाव के साथ चारों सार्वजनिक शौचालयों का नवीनीकरण तथा नई फिटिंग्स लगाने का काम भी किया जाएगा। क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और हरित वातावरण को बेहतर बनाने के लिए बागवानी प्रबंधक एवं उनकी टीम तैनात की गई है। बीच की हरित पट्टी और अन्य हरित क्षेत्रों की सफाई तथा उन्हें विकसित करने का काम जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चांदनी चौक दिल्ली का दिल है और इसकी ऐतिहासिक भव्यता, सांस्कृतिक पहचान तथा जनसुविधाओं को पुनर्स्थापित करना सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने, दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने और कार्यों के दौरान आने वाली बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चांदनी चौक को स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए।

एक नजर

आपसी वित्तीय विवाद को साइबर फ्रॉड का रूप नहीं दिया जा सकता : दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि परिचित पक्षों के बीच आपसी सहमति से हुए वित्तीय लेनदेन को रद्द करने या निजी दीवानी और व्यावसायिक विवादों को सुलझाने के लिए साइबर फ्रॉड शिकायत तंत्र का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने 30 लाख के कथित लेनदेन से जुड़े एक मामले में पिता-पुत्र के दो बैंक खातों पर लगाई गई रोक और लियन को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। मामला 2013 का है। विवाद दिल्ली के करोलबाग स्थित एक संपत्ति की खरीद से शुरू हुआ था, जिसके लिए पिता ने बयाने के तौर पर 30 लाख दिए थे। रजिस्ट्री न होने पर मामला कोर्ट पहुंचा और 16 मार्च, 2026 को दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत 17 मार्च को 30 लाख पिता के खाते में वापस किए गए, जिसे उन्होंने पारिवारिक व्यवस्था के तहत अपने बेटे के खाते में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अगले ही दिन, पैसे भेजने वाली महिला की बेटी ने 'गलती से पैसे ट्रांसफर होने' का दावा करते हुए साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद पिता-पुत्र के खाते फ्रीज कर दिए गए। बाद में शिकायतकर्ता ने अपना बयान बदलते हुए इसे कच्चे सोने में निवेश का मामला बताया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि अभियोजन ने खुद माना है कि यह मामला प्रथम दृष्टया साइबर धोखाधड़ी का नहीं है और शिकायतकर्ता के दोनों बयान आपस में विरोधाभासी हैं। कोर्ट ने कहा कि इस तरह खातों को फ्रीज रखने से परिचित लोगों के निजी विवाद को साइबर अपराध का रूप मिल जाएगा। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि गृह मंत्रालय की 2 जनवरी, 2026 की मानक संचालन प्रक्रिया के तहत बैंक खाते फ्रीज करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 के तहत औपचारिक आदेश जारी करना अनिवार्य है, जिसका इस मामले में पालन नहीं किया गया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने बैंक खातों से रोक हटाने का आदेश देते हुए साइबर शिकायत को पूरी तरह रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि तथ्यात्मक विवादों की जांच जारी रह सकती है और दोनों पक्ष दीवानी या अन्य कानूनी उपायों के तहत अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं।

हाई कोर्ट 23 नवंबर को कृषि भवन मस्जिद गिराए जाने से जुड़ी याचिका पर करेगा सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत कृषि भवन परिसर स्थित 100 साल पुरानी 'कदीमी मस्जिद' (मस्जिद कृषि भवन) के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस अनीश दयाल की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर तय की है, ताकि इसे मस्जिद की देखरेख करने वाली समिति की पहले से लंबित याचिका के साथ सुना जा सके। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुनर्विकास योजना में न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश पर मौखिक रूप से सवाल उठाया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद नहीं है और यह ढांचा कोई संरक्षित स्मारक भी नहीं है। कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह 23 नवंबर की सुनवाई से पहले इस मामले में आवश्यक निर्देश प्राप्त करे। नमाजी मोहम्मद यासिर की ओर से दायर इस नई याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद नहीं है और यह ढांचा कोई संरक्षित स्मारक भी नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील एम सुफियान सिद्दीकी ने तर्क दिया कि 266 वर्ग गज में फैली इस सक्रिय मस्जिद पर ध्वस्तीकरण का खतरा मंडरा रहा है। तत्कालीन अधिकारियों और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्ववर्ती निकाय के बीच हुए 1945 के एक समझौते का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार समझौते की शर्तों के गंभीर उल्लंघन को साबित किए बिना और कब्जा वापस लेने की उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना इसे मनमाने ढंग से नहीं गिरा सकती। याचिका में दिल्ली वक्फ बोर्ड पर भी वैधानिक निष्क्रियता का आरोप लगाया गया है।

गुरुग्राम के क्लब में बाउंसरों ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पीटा

गुरुग्राम। ब्रिस्टल होटल स्थित वाका-वाका नाइट क्लब में पार्टी करने पहुंचे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और उनके दोस्तों के साथ कथित तौर पर बाउंसरों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद घायलों को पहले सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार और टांके लगाने के बाद उन्हें पालम विहार स्थित पार्क अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस को किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार हिमांशु, राहुल, अंशुल और उनके तीन अन्य साथी गुरुवार की रात करीब 11:30 बजे ब्रिस्टल चौक स्थित वाका-वाका क्लब पहुंचे थे। पार्टी के दौरान कुछ प्रशंसकों ने हिमांशु और राहुल को पहचान लिया और उनके साथ फोटो खिंचवाने लगे। इसी दौरान राहुल के हाथ से शीशे का गिलास गिरकर टूट गया। इसे लेकर क्लब स्टाफ और बाउंसरों के साथ कहासुनी हो गई। रात करीब दो से तीन बजे के बीच विवाद बढ़ा और मारपीट शुरू हो गई। बाउंसरों ने राहुल, हिमांशु और उनके दोस्त अंशुल की बेरहमी से पिटाई कर दी। हमले में तीनों घायल हो गए, जबकि हिमांशु और राहुल को गंभीर चोटें आई हैं।

गुरुग्राम के सेक्टर-10 नागरिक अस्पताल में अमृत फार्मेसी शुरू

गुरुग्राम,एजेंसी। सेक्टर-10 स्थित जिला नागरिक अस्पताल में अमृत फार्मेसी का शुक्रवार को उद्घाटन किया गया। लघु सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ही यह उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विधायक मुकेश शर्मा, मेयर राज रानी मल्होत्रा, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ के चेयरमैन रामअवतार गर्ग मौजूद रहे। कार्यक्रम में यमुनानगर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन को लाइव देखा और सुना गया।



मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के 16 जिला नागरिक अस्पतालों में स्थापित अमृत फार्मेसी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक मुकेश शर्मा ने कहा कि अमृत फार्मेसी की शुरुआत आमजन को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध करवाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकारी अस्पतालों में उपचार करवाने आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को अक्सर बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं, जिससे उनके उपचार पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। अमृत फार्मेसी के माध्यम से मरीजों को उचित दरों पर दवाइयां उपलब्ध होंगी और उन्हें राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, किफायती और जनहितकारी बनाना सरकार की प्राथमिकता है। नागरिक अस्पतालों में इस प्रकार की सुविधाओं का विस्तार होने से आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि फार्मेसी का लाभ अधिक से अधिक मरीजों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। मेयर राजरानी मल्होत्रा ने कहा कि अमृत फार्मेसी की शुरुआत स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन के लिए अधिक किफायती और सुलभ बनाने की दिशा में सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रत्येक नागरिक की आवश्यकता हैं और सरकार की ऐसी जनकल्याणकारी पहल से आम लोगों का सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत होगा। कार्यक्रम में एडीसी सोनू भट्ट, सीएमओ डॉ. वीरेंद्र बसवाना, नागरिक अस्पताल सेक्टर 10 से पीएमओ डॉ. नीना गठवाल, डिप्टी सीएमओ डॉ. अनुज गर्ग, डॉ. मनीष, डॉ. हिमानी सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

नूंह के पिनगवां में जुटेंगे प्रदेशभर के इमाम व उलेमा

नूंह,एजेंसी। हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक एवं पूर्व विधायक जाकिर हुसैन के सम्मान में आगामी 23 नवंबर को नूंह जिले के पिनगवां स्थित मदरसा जामिया फातिमा अल जोहरा लिलबनात में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। अकबरपुर रोड स्थित मदरसे में इस कार्यक्रम में तंज़ीम आईमा ए औकाफ, हरियाणा से जुड़े सैकड़ों इमाम और उलेमा शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता तंज़ीम के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना असरुद्दीन तेड़ करेंगे।

शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में मौलाना असरुद्दीन तेड़ ने बताया कि वक्फ बोर्ड प्रशासक जाकिर हुसैन और बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद शाईन ने इमामों के अधिकारों, आर्थिक हितों और कल्याण के लिए पिछले कई वर्षों में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। उनके प्रयासों से इमामों के मानदेय में बढ़ोतरी, हर साल वेतन वृद्धि तथा एक्सग्रेशिया योजना के तहत आश्रित परिवारों को नौकरी देने जैसे अहम फैसले हुए हैं।

उन्होंने कहा कि इमामों और उलेमा की लंबे समय से जुड़ी मांगों पर सकारात्मक पहल हुई है। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा सरकार, वक्फ बोर्ड प्रशासक जाकिर हुसैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद शाईन का तहेदिल से आभार व्यक्त करते हैं। मौलाना असरुद्दीन ने कहा कि तंज़ीम से जुड़े सभी इमाम और उलेमा इन प्रयासों के लिए जाकिर हुसैन का सामूहिक रूप से इस्तकबाल करना चाहते हैं।

भारत ने दुनिया को गंभीर बीमारियों के सस्ते, प्रभावी इलाज का रास्ता दिखाया : डॉ. श्रीनिवास

गुरुग्राम। मेधा के धमाल, नवाचार की ऊंची उड़ान, युवा शक्ति की असीमित कल्पनाशीलता, कुछ कर दिखाने की ललक और कामयाबी की लंबी लकीर खींचने का जुनून...एसजीटी यूनिवर्सिटी के सिनर्जी टेक फेस्ट 2026 में हजारों छात्र-छात्राओं के बीच यही कुछ प्रतिबिंबित होता दिखाई दिया। तीन दिन चले नौवें स्टूडेंट एडिशन का शुक्रवार को भव्य समारोह में समापन हुआ। विभिन्न विभागों, संकायों के मेधावी छात्रों ने 170 से अधिक प्रोजेक्ट स्टालों पर प्रदर्शित किए। भारत सरकार के नीति सलाहकार एवं सीएसआईआर-आईएमटेक रिसर्च काउंसिल के सदस्य डॉ. श्रीनिवास लंका समापन सत्र के मुख्य अतिथि रहे। टेक महिंद्रा के पूर्व सीईओ एवं सर्वम एआई के निदेशक संजय कालरा गेस्ट ऑफ आनर व प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष डॉ. नवनीत कुमार सहगल स्पेशल गेस्ट के रूप में शामिल हुए। एसजीटी यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति पद्मभूषण राम बहादुर राय की गरिमामयी उपस्थिति ने विद्यार्थियों में प्रबल उत्साह का संचार किया।

एसजीटी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) अनिल कुमार कौल के स्वागत भाषण के साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ। कार्यक्रम के चीफ गेस्ट डॉ. श्रीनिवास लंका ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने विश्व को गंभीर बीमारियों के सस्ते और प्रभावशाली इलाज का रास्ता दिखाया। गोरखपुर के मेनिनजाइटिस, विश्वव्यापी टायफाइड और अफ्रीकी देशों के एड्स केसों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भले ही भारत के पास संसाधन सीमित थे पर पैशन के साथ समस्या के समाधान की भारत की युक्ति का असर हर स्तर पर दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज विश्व की 30 प्रतिशत दवाओं और 70 प्रतिशत वैक्सीन की डिमांड भारत पूरी कर रहा है। डॉ. लंका ने कहा कि कुछ आर्थिक विसंगतियां भी हैं। दवाओं की ऊंची कीमत आज भी सबसे बड़ी चुनौती है। स्पेशल गेस्ट डा. नवनीत कुमार सहगल ने सिनर्जी टेक फेस्ट की सराहना करते हुए कहा कि इसमें 170 से अधिक प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए गए, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इच्छा शक्ति के साथ एसजीटी यूनिवर्सिटी में प्रतिभा को यथार्थ के धरातल पर उतारने का अवसर भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आज स्टार्टअप का विश्व का सबसे बड़ा इको सिस्टम भारत में है। 50 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती कुछ देशों पर भारत की तकनीकी निर्भरता कम करने की है।

साइबर अपराधियों ने तीन लोगों को बनाया शिकार, करीब 41 लाख रुपये की ठगी

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे



नोएडा। उत्तर प्रदेश के जनपद गौतमबुद्धनगर नोएडा में साइबर अपराधियों ने विभिन्न जगहों पर रहने वाले तीन लोगों को अपना शिकार बनाया। बदमाशों ने इन्वेस्ट कर मोटी रकम कमाने की लालच देकर, डीमैट खाथा खुलवाने के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाया। पुलिस उपायुक्त साइबर क्राइम शैव्या गोयल ने बताया कि बीती रात रमेश चंद सोनी ने साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहते हैं। पीड़ित के अनुसार व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किया तथा कहा कि शेयर मार्केट में निवेश करने से उन्हें काफी मुनाफा होगा। पीड़ित के अनुसार वह उनकी बातों में आ गए तथा धीरे-धीरे करके उन्होंने उनके बताए हुए विभिन्न खातों में 17 लाख 39 हजार 843 रूपये ट्रांसफर कर दिया। पीड़ित के अनुसार उनकी रकम ऐप पर बढ़ी हुई दिखाई दे रही थी। जब उन्होंने अपना पैसा निकालने का प्रयास किया तो साइबर अपराधियों ने उनको ग्रुप से बाहर निकाल दिया। डीसीपी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

डीसीपी ने बताया कि अजय कुमार सिंह पुत्र गोरखनाथ सिंह ने बीती रात को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह छलेरा गांव में रहते हैं। पीड़ित के अनुसार अज्ञात साइबर अपराधियों ने उनसे संपर्क किया तथा टेलीग्राम के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी। पीड़ित के अनुसार वह उनकी बातों में आ गए तथा उन्होंने नौ लाख 51 हजार 473 रूपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। पीड़ित के अनुसार आरोपितों ने धोखाधड़ी कर उनकी रकम हड़प ली। डीसीपी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदीप राय ने बीती रात को साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि ऋषभ उर्फ मोहम्मद शरीफ नामक व्यक्ति उनके घर पर आया। उसने उनसे डीमैट खाता खोलने के लिए बात की। उन्होंने उसे अपना फोन दे दिया। पीड़ित के अनुसार आरोपित ने उनके फोन का क्लोन बना लिया और उनके खाते से लगभग 14 लाख रुपये निकाल लिया। उन्होंने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हाई कोर्ट ने दहेज के लिए बहुओं की हत्या को भारतीय समाज के लिए 'सामूहिक शर्म' और 'दयनीय वास्तविकता' बताया

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दहेज प्रताड़ना और उसके चलते नवविवाहिताओं की होने वाली मौतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे भारतीय समाज की एक दुखद और दयनीय हकीकत तथा सामूहिक शर्म का विषय बताया है। साल 2001 के एक दहेज हत्या मामले से जुड़ी अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विमल कुमार यादव की पीठ ने ये तीखी टिप्पणियां कीं। कोर्ट ने कहा कि शादी में उपहारों का लेन-देन दुनिया भर में प्रचलित है, लेकिन मांगें पूरी न होने पर दुल्हनों को प्रताड़ित करना या मार डालना एक घृणित अपराध है, जो हमारे समाज में गहराई तक फैला हुआ है।



कोर्ट ने कहा कि हर महिला खुशहाल जीवन के सपने लेकर ससुराल जाती है, लेकिन वहां उस पर अपने माता-पिता से पैसे और सामान लाने का लगातार दबाव बनाया जाता है। इसके चलते कई महिलाओं को आत्महत्या, हत्या, तलाक या जीवन भर की खामोश प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि इस तरह की क्रूरता अक्सर घर की चारदीवारी के भीतर होती है, जिसके कारण समय रहते इसका पता नहीं चल पाता। मामला सोनिया नाम की एक महिला की मौत से जुड़ा है, जिसने शादी के दो साल के भीतर अक्टूबर, 2001 में आत्मदाह कर लिया था। मृतका के माता-पिता ने आरोप लगाया था कि ससुराल वाले मोटरसाइकिल, गैस चूल्हा, पानी की मोटर और 25,000 नकद के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे थे। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में पति जय देव और उसके परिवार के दो सदस्यों (छोटे लाल और वीरू) को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और 304बी का दोषी ठहराया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने पाया कि महिला की मौत से ठीक पहले दहेज मांगने के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हैं। इस आधार पर कोर्ट ने पति के पिता और भाई को सभी आरोपों से बरी कर दिया। वहीं, पति के खिलाफ लगातार कलह और मायके से वापस ले जाते समय अच्छे व्यवहार के वादे को तोड़ने के सबूतों को देखते हुए उसकी क्रूरता की सजा को बरकरार रखा और दहेज हत्या की धारा को बदलकर आत्महत्या के लिए उकसाने (धारा 306) में तब्दील कर दिया।

द्वारका एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार ट्राले ने तीन गाड़ियों को मारी टक्कर

गुरुग्राम। द्वारका एक्सप्रेसवे पर गुरुवार देर रात तेज रफ्तार ट्राले ने जमकर कहर बरपाया। मानेसर की तरफ से दिल्ली जा रहे एक लोडेड ट्राले ने तीन गाडियों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक कार एक्सप्रेसवे की दोनों सडक़ों के बीच बनी ग्रीन बेल्ट और ड्रेन में जा गिरी, जबकि दो कैब बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे में कार चालक घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी ट्राला चालक मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा द्वारका एक्सप्रेसवे पर एवीएल-36 सोसाइटी के नजदीक हुआ। एक लोडेड ट्राला मानेसर की ओर से दिल्ली के द्वारका की तरफ जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्राले ने रास्ते में तीन वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर लगते ही एक कार अनियंत्रित होकर दोनों तरफ की सडक़ों के बीच बने नाले में जा गिरी। वहीं, दो कैब भी टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही सेक्टर-37 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

गुरुग्राम में मेटा के कार्यालय पर हरियाणा युवा कांग्रेस ने जड़ा ताला

गुरुग्राम। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब एवं राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा के इंस्टाग्राम अकाउंट बंद किए जाने के विरोध में हरियाणा युवा कांग्रेस ने मेटा के कार्यालय पर ताला जडक़र अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। इस दौरान युवा कांग्रेस ने मेटा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे विपक्ष की आवाज दबाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला गंभीर मामला बताया। इस दौरान स्थानीय थाना पुलिस ने कांग्रेसियों को डिटेन कर लिया। बाद में सभी को छोड़ा गया।

युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निशित निशित कटारिया ने कहा कि आज देश में एक अजीब स्थिति पैदा की जा रही है। जो भी सरकार से सवाल पूछता है, जो भी युवाओं के रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी और आम जनता के मुद्दों पर आवाज उठाता है, उसकी आवाज को दबाने के प्रयास किए जाते हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो लोकतंत्र में जनता अपनी बात कहां रखेगी। उन्होंने सवाल किया कि आखिर मेटा ने भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा के इंस्टाग्राम अकाउंट किसके आदेश पर बंद किए। क्या मेटा किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है। यदि कार्रवाई किसी नियम के तहत हुई है तो उसके स्पष्ट कारण सार्वजनिक किए जाएं। देश को यह जानने का अधिकार है कि आखिर विपक्ष की आवाज पर बार-बार कार्रवाई क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि मेटा भारत में कारोबार करने वाली एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी है। उसका दायित्व एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी डिजिटल मंच उपलब्ध करवाना है। उसे किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में खड़े होने के बजाय अपने नियमों का निष्पक्ष पालन करना चाहिए। भाजपा नेताओं के अकाउंट और विपक्षी नेताओं के अकाउंट के साथ होने वाले व्यवहार में कोई अंतर है तो मेटा को उसका जवाब देना चाहिए।

नूंह पुलिस ने साड़ी व फर्नीचर बेचने के नाम पर ठगी करते तीन साइबर ठग पकड़े

नूंह,एजेंसी। नूंह जिला पुलिस की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अलग-अलग दो मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन और फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर साड़ी और फर्नीचर बेचने का झांसा देते थे और लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी करते थे।

वहीं, तीसरा आरोपी साइबर ठगी में संलिप्त लोगों को फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध करवाता था। पुलिस प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि साइबर क्राइम थाना पुलिस की एक टीम जमालगढ़ रोड पर लुहिंगा कलां मोड़, पुन्हाना के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि गांव लहरवाड़ी निवासी हसीन और शेम खां मोबाइल फोन और फर्जी सिम कार्ड के माध्यम से लोगों को साड़ी व फर्नीचर बेचने का झांसा देकर ठगी करते हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने जमालगढ़ रोड के नजदीक दबिश देकर दोनों आरोपियों को काबू कर लिया। पुलिस द्वारा आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच करने पर ऑनलाइन ठगी से जुड़े कई संदिग्ध तथ्य सामने आए। शेम खां के कब्जे से लावा कंपनी का मोबाइल फोन बरामद हुआ। जांच में फोन में 'होम डेकॉर फर्नीचर' नाम से प्रोफाइल मिली, जिस पर फर्नीचर बेचने से संबंधित फोटो और वीडियो मौजूद थे। इसके अलावा फेसबुक पर 'आरोही अग्रवाल' नाम से भी आईडी मिली। वहीं, दूसरे आरोपी के मोबाइल फोन में इंस्टाग्राम पर 'रुक्मिणी सिल्क' नाम से अकाउंट और व्हाट्सएप पर इसी नाम से प्रोफाइल मिली। फोन में महिलाओं द्वारा साड़ी पहनकर प्रचार करने वाले वीडियो और फोटो के साथ लोगों से साड़ी बेचने के नाम पर हुई संदिग्ध चैट भी मिली। जांच के दौरान दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन में लगी सिम दूसरे व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत पाई गईं। दूसरे मामले में पुलिस टीम अडबर चौक के पास गश्त कर रही थी।

पुलिस की टोपी क्या यातायात नियम तोड़ने का लाईंसस...

गुरुग्राम। पुलिस की टोपी की अहमियत जाननी है तो सिविल लाइन क्षेत्र में खड़ी उस कार से जानिये, जिसकी नंबर प्लेट से आगे-पीछे के आधे नंबर मिटाने पर भी पास में खड़े पुलिस कर्मियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्योंकि उसके आगे डैशबोर्ड पर पुलिस की टोपी रखी थी। आगे से पांच डिजिट का ब्लैक कलर उतार रखा था और पीछे से चार डिजिट का ब्लैक कलर उतार रखा था।

शहर में लगे कैमरे से चालान ना कटे, इससे बचने वाला यह कार चालक बेधडक़ निकल ही रहा होगा। कैमरे को तो चकमा दे दिया, मगर सिविल लाइन में पुलिस बूथ से चंद कदम की दूरी पर खड़ी यह कारपुलिसकर्मियों को नजर नहीं आई। अगर आई होगी तो उसे अनदेखा कर दिया होगा। क्योंकि उसके भीतर पुलिस की टोपी रखी थी। क्या पुलिस की टोपी रख देने मात्र से किसी भी यातायात के नियम की धज्जियां उड़ाने की परमिशन मिल जाती है। जिला सैनिक बोर्ड के पास बने पुलिस बूथ के पास का है। पुलिस बूथ के ठीक पास में यह कार खड़ी थी। साफ लग रहा था कि इसके नंबर प्लेट के साथ जान-बूझकर छेड़छाड़ की गई है।

सवाल यह उठता है कि क्या पुलिस की टोपी, वर्दी या पुलिस का कोई निशान रख देने से कोई



भी व्यक्ति कानून से ऊपर हो जाता है। नियमों के मुताबिक, नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करना, नंबर मिटाना या उसे अपठनीय बनाना मोटर वाहन अधिनियम के तहत गंभीर अपराध है। ऐसा करने पर भारी जुर्माना, वाहन जब्ती और कई मामलों में मुकदमा तक दर्ज हो सकता है।

ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि चालान से बचा जा सके, टोल से बचा जा सके या किसी अपराध के बाद वाहन की पहचान न हो सके। इसलिए पुलिस को ऐसे वाहनों पर सबसे ज्यादा नजर रखनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या यह कार किसी पुलिसकर्मी की है या किसी ऐसे व्यक्ति की है जो पुलिस की टोपी रखकर पुलिस को गुमराह कर रहा है। दोनों ही स्थितियों में यह मामला गंभीर है। अगर यह कार पुलिसकर्मी की है तो नियम तोडऩे पर उस पर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यह कार किसी आम व्यक्ति की है जो पुलिस की टोपी का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो यह पुलिस की छवि का दुरुपयोग है और इस पर भी कार्रवाई बनती है।

शांति की आड़ में महाशक्तियों की नई बिसात

अशोक भाटिया



अंतरराष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं, जो केवल एक घटना को दर्ज नहीं करतीं, बल्कि आने वाले दशकों की भू-राजनीतिक दिशा तय करती हैं। चीन के शेनझेन स्थित कायलिन विला में एपेक शिखर सम्मेलन के दौरान एक ही गोलमेज पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात ऐसी ही एक युगांतरकारी परिघटना है। लगभग अस्सी मिनट तक चली इस त्रिपक्षीय वार्ता के बाद जारी किए गए चार-सूत्रीय 'शांति घोषणापत्र' को वैश्विक मीडिया के एक बड़े वर्ग द्वारा परमाणु हथियारों पर लगाम लगाने और विश्व शांति की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। परंतु कूटनीति की बारीक परतों को उधेड़कर देखें, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या दुनिया की तीन सबसे बड़ी परमाणु महाशक्तियां वास्तव में हथियारों की होड़ समाप्त करने के लिए एकजुट हुई हैं, या फिर यह 1945 के 'याल्टा सम्मेलन' का एक नया संस्करण है, जहाँ बड़ी ताकतें बंद कमरे में बैठकर आपस में दुनिया के प्रभाव क्षेत्रों का बंटवारा करने बैठी हैं? इस बैठक के सबसे चर्चित पहलू यानी परमाणु निरस्त्रीकरण की वास्तविकता पर गौर करना आवश्यक है। बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन और परमाणु मुक्त विश्व की वकालत की। सुनने में यह विचार अत्यंत आदर्शवादी और सुखद प्रतीत होता है, लेकिन इसके ठीक विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक के बाद यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं किया कि परमाणु हथियारों को पूरी तरह छोड़ना लगभग नामुमकिन है। यही विरोधाभास इस पूरे घोषणापत्र की असलियत को उजागर करता है। यदि हम घोषणापत्र की भाषा को ध्यान से पढ़ें, तो इसमें परमाणु हथियारों की संख्या घटाने या नई हथियार संधि करने जैसा कोई ठोस और बाध्यकारी वादा नहीं है। इसमें केवल 'परमाणु जोखिम कम करने की बातचीत' और रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने की बात कही गई है। 'न्यू स्टार्ट' संधि की समाप्ति के बाद वैश्विक परमाणु नियंत्रण व्यवस्था में जो शून्य पैदा हुआ था, उसे भरने के बजाय तीनों महाशक्तियों ने केवल संवाद की औपचारिकता निभाई है। विडंबना यह है कि एक तरफ चीन परमाणु मुक्त विश्व की अपील कर रहा है, तो दूसरी तरफ वह स्वयं अपने परमाणु शस्त्रागार का सबसे तेज गति से विस्तार कर रहा है। अमेरिका और रूस के पास पहले से ही दुनिया के नब्बे प्रतिशत से अधिक परमाणु हथियार मौजूद हैं।

ऐसे में, बिना किसी ठोस कटौती के निरस्त्रीकरण की बातें करना वैश्विक जनमत को भ्रमित करने जैसा ही है। शेनझेन बैठक का सबसे चौंकाने वाला और कम चर्चित पहलू वह है, जहाँ इन तीनों वैचारिक रूप से विरोधी महाशक्तियों के हित आपस में पूरी तरह मेल खाते हैं। यह पहलू है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और वैश्विक न्याय प्रणाली को कमजोर करने का साझा प्रयास। घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात तो कही गई है, लेकिन इसके साथ ही तीनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ एक अभूतपूर्व एकजुटता दिखाई है। यह किसी से छिपा नहीं है कि रूस, अमेरिका और चीन, तीनों ही अपने-अपने कारणों से अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों और संधियों की निगरानी से बाहर रहना चाहते हैं। जब विश्व की तीन सबसे ताकतवर सरकारें मिलकर किसी वैश्विक न्यायिक संस्था के अधिकारों को सीमित करने पर सहमत होती हैं, तो यह छोटे और विकासशील देशों के लिए खतरे की घंटी बन जाता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि महाशक्तियां एक ऐसी व्यवस्था गढ़ना चाहती हैं, जहाँ नियम-कानून केवल कमजोर राष्ट्रों पर लागू हों, जबकि ताकतवर देश अपनी शर्तों पर दुनिया चलाएं। इसके अतिरिक्त, यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व के संकट और ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे ज्वलंत वैश्विक मुद्दों पर इस घोषणापत्र की चुप्पी यह साबित करती है कि तीनों नेताओं ने उन विवादित विषयों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिन पर उनके बीच टकराव की संभावना थी। इसे कूटनीति की भाषा में 'सुविधाजनक समझौता' कहा जाता है, जहाँ वास्तविक समस्याओं को हल करने के बजाय केवल अपनी छवि चमकाने वाले बिंदुओं पर सहमति बनाई जाती है। भारत के दृष्टिकोण से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के नीति निर्माताओं, उद्योग जगत और आम नागरिकों के लिए इस त्रिपक्षीय जुगलबंदी के गहरे निहितार्थ हैं। भारत की विदेश नीति सदैव रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की पक्षधर रही है।

यदि अमेरिका, रूस और चीन मिलकर किसी 'बिग-थ्री' क्लब का निर्माण करते हैं, तो यह भारत के बहुध्रुवीय विश्व के सपने के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। विशेष रूप से चीन की भूमिका भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। शेनझेन की मेज पर बैठकर चीन ने स्वयं को एक शांतिदूत और जिम्मेदार वैश्विक नेता के रूप में पेश करने का सफल प्रयास किया है, जबकि वास्तविकता यह है कि उत्तरी सीमाओं पर उसकी आक्रामकता और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी विस्तारवादी नीतियां आज भी क्षेत्र की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई हैं। जब अमेरिका और रूस भी चीन को वैश्विक व्यवस्था का एक बराबर का साझेदार मानने लगते हैं, तो एशिया में शक्ति संतुलन प्रभावित होना तय है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि महाशक्तियों की इस नई दोस्ती की कीमत किसी भी रूप में एशियाई देशों की संप्रभुता या हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्वतंत्रता को न चुकानी पड़े। इसके साथ ही, रूस के साथ भारत के पारंपरिक और भरोसेमंद संबंधों को भी इस बदलते समीकरण के बीच नए सिरे से साधने की आवश्यकता होगी।

हालांकि, इस घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा पक्ष भी है, जो भारत के हर नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी और रसोई के बजट को प्रभावित करता है। शेनझेन घोषणापत्र में तीनों महाशक्तियों ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाने और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने पर सहमति जताई है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का अस्सी प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात करता है। यदि इस सहमति के परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें नियंत्रित रहती हैं और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला सुचारू बनी रहती है, तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर होगी। इससे देश में महंगाई को काबू में रखने, परिवहन लागत घटाने और बुनियादी ढांचे की विकास योजनाओं को गति देने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, यदि अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव कम होता है, तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता आएगी, जिसका लाभ भारतीय निर्यातकों और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी मिल सकता है। साथ ही, घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का जो जिक्र किया गया है, भारत को उसका कूटनीतिक लाभ उठाते हुए अपनी स्थायी सदस्यता के दावे को और अधिक मुखरता से वैश्विक मंच पर रखना होगा। दरअसल शेनझेन की इस ऐतिहासिक बैठक को विश्व शांति के अंतिम समाधान के रूप में देखने की भूल नहीं की जानी चाहिए। इतिहास गवाह है कि जब भी महाशक्तियों ने बंद कमरों में बैठकर दुनिया की तकदीर लिखने की कोशिश की है, उसका परिणाम नए शीत युद्ध, अविश्वास या क्षेत्रीय अस्थिरता के रूप में ही सामने आया है। सच्ची और स्थायी वैश्विक शांति केवल तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के हाथ मिलाने या चार-सूत्रीय घोषणापत्र जारी करने से स्थापित नहीं हो सकती। परमाणु हथियारों का खतरा तभी समाप्त होगा, जब महाशक्तियां अपने शस्त्रागारों में वास्तविक, समयबद्ध और पारदर्शी कटौती करेंगी और इसके सत्यापन के लिए स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय निगरानी को स्वीकार करेंगी। इसके साथ ही, इक्कीसवीं सदी की किसी भी नई वैश्विक व्यवस्था में भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र और 'ग्लोबल साउथ' के विकासशील देशों की आवाज को बराबर का सम्मान मिलना अनिवार्य है। शेनझेन की मेज से निकला संदेश स्पष्ट है कि दुनिया एक बड़े भू-राजनीतिक बदलाव के मुहाने पर खड़ी है, और इस बदलती बिसात पर भारत को अपनी कूटनीतिक सूझबूझ, आर्थिक मजबूती और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पहले से कहीं अधिक सतर्क और सक्रिय रहना होगा।

देश के व्यापक आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में 4952 आतंकियों, उग्रवादियों और चरमपंथियों के मारे जाने का आंकड़ा सामने आया है। इसमें जम्मू-कश्मीर के 1891 आतंकी शामिल हैं। बाकी आंकड़े देश के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय उग्रवादी और चरमपंथी संगठनों के विरुद्ध चलाए गए अभियानों से जुड़े हैं। यह तस्वीर बताती है कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न मोर्चों पर एक साथ चल रही है। जम्मू-कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35ए हटने के बाद आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई का स्वरूप व्यापक हुआ। सुरक्षा बलों के अभियानों के साथ आतंकियों की आर्थिक सहायता, स्थानीय सहयोगियों, भर्ती तंत्र और संगठनात्मक नेटवर्क पर कार्रवाई तेज हुई। वर्ष 2018 में 228 आतंकवादी गतिविधियों की पहल से जुड़ी घटनाएं दर्ज हुई थीं, जो 2025 में घटकर 12 रह गईं। इस श्रेणी में लगभग 95 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई। संगठित पत्थरबाजी भी घाटी के सुरक्षा परिदृश्य में बड़ा बदलाव दिखाती है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2018 में 1328 घटनाएं दर्ज हुई थीं, जबकि 2023 में ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई। 2024 में भी 15 जुलाई तक संगठित पत्थरबाजी की कोई घटना दर्ज नहीं हुई थी। स्थानीय युवाओं की आतंकी संगठनों में भर्ती वर्ष 2018 के करीब 199 के आंकड़े से घटकर 2023 में 19 से 22 और 2024 में चार से सात के बीच पहुंच गई।

जम्मू-कश्मीर में अब आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंची

डॉ. मयंक चतुर्वेदी



जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक दशक पहले जिस घाटी में आतंकी संगठनों की धमक, अलगाववादी गतिविधियां, पत्थरबाजी और युवाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाने का तंत्र सुरक्षा बलों के सामने लगातार चुनौती खड़ा करता था, वहां आज स्थानीय आतंकी भर्ती लगभग शून्य पर पहुंचने और सक्रिय स्थानीय आतंकियों के नेटवर्क के कमजोर पड़ने के संकेत हैं। दरअसल, कुलगाम में लश्कर-ए-तैयबा के आखिरी ज्ञात सक्रिय स्थानीय कमांडर मोहम्मद लतीफ भट का मारा जाना इस बदलाव की महत्वपूर्ण कड़ी है। 2014 से अब तक जम्मू-कश्मीर में 1891 आतंकियों का सफाया हो चुका है, जबकि इसी अवधि में देशभर में आतंकियों, उग्रवादियों और चरमपंथियों की मौत का आंकड़ा 4952 तक पहुंचा है। सुरक्षा बलों की सफलता अब आतंकवाद के पूरे तंत्र को समाप्त करने की कसौटी पर है। बंदूक, बारूद और आतंकियों के ठिकानों पर प्रहार के साथ कट्टरपंथी विचारधारा, भर्ती तंत्र, आर्थिक सहायता, सीमा पार संचालन और डिजिटल प्रचार के विरुद्ध भी निर्णायक लड़ाई आवश्यक हो गई है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल (एसएटीपी) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014 से जम्मू-कश्मीर में 1891 आतंकवादी मारे गए हैं। वर्ष 2014 में 114, 2015 में 115, 2016 में 165, 2017 में 220 और 2018 में सर्वाधिक 271 आतंकियों का सफाया हुआ। इसके बाद 2019 में 163, 2020 में 232, 2021 और 2022 में 193-193 आतंकवादी मारे गए। वर्ष 2023 में यह संख्या 87, 2024 में 69 और 2025 में 46 रह गई। 2026 में अब तक 24 आतंकियों का सफाया किया जा चुका है। 2018 की तुलना में 2025 में आतंकियों के मारे जाने की संख्या में करीब 83 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। यह आंकड़ा आतंकवादी संगठनों की क्षमता, स्थानीय नेटवर्क और उनके संचालन पर लगातार पड़ते दबाव को दर्शाता है।

देश के व्यापक आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में 4952 आतंकियों, उग्रवादियों और चरमपंथियों के मारे जाने का आंकड़ा सामने आया है। इसमें जम्मू-कश्मीर के 1891 आतंकी शामिल हैं। बाकी आंकड़े देश के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय उग्रवादी और चरमपंथी संगठनों के विरुद्ध चलाए गए अभियानों से जुड़े हैं। यह तस्वीर बताती है कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न मोर्चों पर एक साथ चल रही है। जम्मू-कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35ए हटने के बाद आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई का स्वरूप व्यापक हुआ। सुरक्षा बलों के अभियानों के साथ आतंकियों की आर्थिक सहायता, स्थानीय सहयोगियों, भर्ती तंत्र और संगठनात्मक नेटवर्क पर कार्रवाई तेज हुई। वर्ष 2018 में 228 आतंकवादी गतिविधियों की पहल से जुड़ी घटनाएं दर्ज हुई थीं, जो 2025 में घटकर 12 रह गईं। इस श्रेणी में लगभग 95 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई। संगठित पत्थरबाजी भी घाटी के सुरक्षा परिदृश्य में बड़ा बदलाव दिखाती है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2018 में 1328 घटनाएं दर्ज हुई थीं, जबकि 2023 में ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई। 2024 में भी 15 जुलाई तक संगठित पत्थरबाजी की कोई घटना दर्ज नहीं हुई थी। स्थानीय युवाओं की आतंकी संगठनों में भर्ती वर्ष 2018 के करीब 199 के आंकड़े से घटकर 2023 में 19 से 22 और 2024 में चार से सात के बीच पहुंच गई। जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने इस संबंध में बताया कि पिछले दो वर्षों में लश्कर-ए-तैयबा में केवल दो कश्मीरी युवक शामिल हुए और दोनों मारे जा चुके हैं। उमर निसार और मोहम्मद लतीफ भट का सफाया स्थानीय भर्ती तंत्र के लिए बड़ा झटका है। स्थानीय आतंकी भर्ती लगभग शून्य पर पहुंचने का दावा घाटी में सुरक्षा रणनीति के बदले स्वरूप को रेखांकित करता है। इसे लेकर एयरफोर्स से सेवानिवृत्त, रक्षा विशेषज्ञ डॉ. राजेश शर्मा का हिन्दुस्थान समाचार से कहा, 'सुरक्षा बल आतंकियों को मार गिरा सकते हैं, उनके ठिकाने ध्वस्त कर सकते हैं, हथियार और धन की आपूर्ति रोक सकते हैं, किंतु आतंकवाद को जन्म देने वाली मानसिकता पर प्रहार के बिना स्थायी समाधान कठिन है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और इस्लामिक स्टेट जैसे संगठन धार्मिक पहचान और कट्टरपंथी व्याख्याओं का इस्तेमाल युवाओं को हिंसा की ओर धकेलने के लिए करते रहे हैं। ऐसे में निर्दोष नागरिकों की हत्या, आत्मघाती हमले और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध हिंसा को धार्मिक (मजहबी) उद्देश्य का आवरण देने वाली विचारधारा को चुनौती देना अब सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा होना चाहिए। इसमें परिवार, धार्मिक संस्थाओं, शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है।'

उन्होंने कहा, 'आतंकवादी मोहम्मद लतीफ़ भट जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में एक मस्जिद के अंदर छिपा हुआ था, उसे आत्मसमर्पण करने का मौका दिया गया, लेकिन उसने मना कर दिया उसे शायद लगा था कि मस्जिद के अंदर छिपने से वह सुरक्षित रहेगा। हमारी भारतीय सेना ने मस्जिद को बिना किसी नुकसान पहुँचाए आतंकवादी मोहम्मद लतीफ़ भट को मार गिराया। अब तक न जाने कितनी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें आतंकवादियों ने धार्मिक स्थलों का सहारा लिया है, इसलिए आज यह जरूरी हो जाता है कि मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध वर्ग, धार्मिक विद्वानों, इमामों और मदरसों के संचालकों की भी जिम्मेदारी है कि हिंसा को धार्मिक मान्यता देने वाले तत्वों के विरुद्ध स्पष्ट आवाज उठाएं और युवाओं को शिक्षा, रोजगार तथा राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करें।' दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में लतीफ भट के खात्मे के बाद सुरक्षा बलों के समन्वित अभियान की सराहना की है। आतंकवाद के विरुद्ध सरकार की रणनीति आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराने तक सीमित नहीं है। आतंकवादियों के लिए ठिकाने उपलब्ध कराने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स, आर्थिक मदद पहुंचाने वाले नेटवर्क, हथियार और संचार साधन उपलब्ध कराने वाले तंत्र तथा सीमा पार से निर्देश देने वाले संचालक भी कार्रवाई के दायरे में हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीजीपी प्रभात के अनुसार, यूएपीए के तहत 2025 में 240 आरोपित गिरफ्तार किए गए, जबकि 2026 में 18 नवंबर तक 210 गिरफ्तारियां हुईं। आतंकवाद से जुड़ी 155 संपत्तियां पिछले वर्ष कुर्क की गईं और इस वर्ष अब तक 122 संपत्तियों पर कार्रवाई हुई। दो वर्षों में 450 गिरफ्तारियां और 277 संपत्तियों पर कार्रवाई आतंकवाद के संसाधन तंत्र पर प्रहार का हिस्सा है। आतंकवाद के विरुद्ध अभियान में जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीआरपीएफ और खुफिया एजेंसियों का तालमेल भी मजबूत किया जा रहा है। पुलिस प्रशिक्षण में जंगल और पर्वतीय युद्ध, साइबर अपराध, मोबाइल फोरेंसिक, आर्थिक अपराध, टेरर फंडिंग, ड्रोन तथा आधुनिक तकनीक पर जोर दिया गया है। ग्रे हाउंड में 512 पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण और एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, डार्क वेब तथा क्रिप्टोकरेंसी जैसे विषयों पर 1201 पुलिसकर्मियों का उन्नत प्रशिक्षण बदलती सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप तैयारी का संकेत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के विरुद्ध देशव्यापी समन्वित रणनीति पर जोर देते हुए कहा कि विभिन्न राज्यों की पुलिस के प्रयासों को एक साझा व्यवस्था में जोड़ना आवश्यक है। कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से कामाख्या तक आतंकवाद से मुकाबले के लिए हर पुलिस थाने के स्तर पर एकसमान रणनीति और मजबूत सूचना तंत्र विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी घटना होने से पहले आतंकियों को पकड़ना सुरक्षा एजेंसियों की सफलता का महत्वपूर्ण पैमाना है। आतंकवादी नेटवर्क के विरुद्ध कार्रवाई में सूचना साझा करने, वित्तीय जांच एजेंसियों के समन्वय, राज्य पुलिस और आतंकवाद निरोधक दस्तों की क्षमता तथा साइबर विशेषज्ञ इकाइयों को मजबूत करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की क्षमता बढ़ाने, विशेष न्यायालय स्थापित करने, आतंकवादी फंडिंग रोकने और विदेशों में छिपे अपराधियों को भारत वापस लाने के प्रयासों को भी इसी रणनीति का हिस्सा बताया गया है।

विचार

मिस्टर राहुल, लोकतंत्र आपकी राजनीतिक उपस्थिति का मोहताज नहीं!

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

लोकतंत्र की शक्ति किसी नेता के दावे, राजनीतिक दल के वर्चस्व अथवा परिवार की विरासत में न होकर जनता के अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता और सत्ता परिवर्तन की स्वतंत्रता में निहित होती है। भारत इसका सशक्त उदाहरण है, जहां चुनावी हार-जीत, राजनीतिक उत्थान-पतन और सत्ता परिवर्तन के बीच लोकतंत्र की यात्रा निरंतर जारी है। ऐसे में राहुल गांधी का यह कहना कि विपक्ष चुनावों का बहिष्कार कर दे तो भारतीय लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था की व्यापकता और संवैधानिक शक्ति को कम करके आंकने जैसा है। विपक्ष लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है, मगर कोई एक राजनीतिक दल लोकतंत्र का पर्याय नहीं हो सकता। शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रॉबर्ट ए. पेप के साथ संवाद के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष चुनावों का बहिष्कार कर दे तो उसी क्षण भारतीय लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना, मतदाता सूची की त्रुटियां सामने लाना और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगना विपक्ष का अधिकार है। संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करना भी उसकी जिम्मेदारी है मगर इन अधिकारों के आधार पर लोकतंत्र को अपनी राजनीतिक उपस्थिति से जोड़ना अतिशयोक्ति है क्योंकि भारत का लोकतंत्र किसी नेता, दल अथवा राजनीतिक परिवार की सक्रियता पर निर्भर नहीं। वस्तुत: संविधान की प्रस्तावना के शब्द 'हम भारत के लोग' लोकतंत्र की मूल भावना स्पष्ट करते हैं। सत्ता का स्रोत जनता है और राजनीतिक दल नागरिकों की आकांक्षाओं को शासन तक पहुंचाने का माध्यम हैं। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, जबकि अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी देता है। इस व्यवस्था में किसी दल को लोकतंत्र पर स्थायी अधिकार प्राप्त नहीं है। विपक्ष की भागीदारी लोकतंत्र को प्रतिस्पर्धात्मक बनाती है। वह सरकार को जवाबदेह बनाता है, जनता के सामने विकल्प रखता है और नीतियों की समीक्षा करता है। किसी बड़े विपक्षी दल के चुनाव से हटने पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकते हैं, किंतु किसी दल की अनुपस्थिति संवैधानिक व्यवस्था का अंत नहीं है। राजनीतिक चुनौती और लोकतंत्र की समाप्ति दो अलग-अलग स्थितियां हैं। भारत का इतिहास इसका प्रमाण है। 1952, 1957 और 1962 में कांग्रेस की सरकार बनी, फिर 1967 में अनेक राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और गैर-कांग्रेसी सरकारों का दौर शुरू हुआ। 1977 में जनता ने केंद्र में भी सत्ता परिवर्तन कर दिया। कांग्रेस पराजित हुई, जनता पार्टी सत्ता में आई। यही भारत की लोकतांत्रिक विशेषता है, जहां मतदाता किसी दल या नेता से बंधा नहीं है और उसे अपना निर्णय बदलने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र पर वास्तविक संकट तब आता है, जब नागरिक स्वतंत्रता बाधित हो, अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगे, विपक्षी आवाजें दबाई जाएं, प्रेस पर सेंसरशिप लागू हो और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कठिन बना दिया जाए। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू आपातकाल इसी का गंभीर उदाहरण है।

उस दौर में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां हुईं, प्रेस की स्वतंत्रता सीमित की गई और नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगे। सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपक्ष को संघर्ष करना पड़ा। 1977 में जनता ने चुनाव के माध्यम से अपना निर्णय सुनाया और इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। यह प्रसंग बताता है कि लोकतंत्र की रक्षा सत्ता और विपक्ष, दोनों की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी निर्वाचन आयोग और चुनावी प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। मतदाता सूची में त्रुटियां, संदिग्ध प्रविष्टियां, तस्वीरों की गड़बड़ी और मताधिकार से जुड़ी शिकायतें गंभीर विषय हैं। इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निर्वाचन आयोग को पारदर्शिता के साथ जवाब देना चाहिए। मगर आरोपों के साथ प्रमाण भी आवश्यक हैं। किसी सूची में गलत तस्वीर प्रशासनिक त्रुटि हो सकती है, दोहरी प्रविष्टि गंभीर समस्या हो सकती है, मगर हर त्रुटि को सुनियोजित चुनावी धांधली का प्रमाण मानना उचित नहीं। लोकतांत्रिक संघर्ष तथ्यों, प्रमाणों और संवैधानिक प्रक्रियाओं से मजबूत होता है, न कि बार-बार आरोपों की पुनरावृत्ति से। कांग्रेस ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बड़ी पराजय का सामना किया। चुनाव परिणाम जनता की प्राथमिकताओं, अपेक्षाओं और राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब होते हैं। किसी दल को हार मिलने पर संगठन, नेतृत्व, नीतियों और जनसंपर्क का आकलन करना चाहिए। जनता बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर समाधान चाहती है। संगठन की मजबूती, नेतृत्व की विश्वसनीयता और कार्यकर्ताओं की सक्रियता चुनावी सफलता के महत्वपूर्ण आधार हैं। यह तो कांग्रेस और राहुल गांधी को समझना ही होगा कि राजनीतिक प्रासंगिकता आरोपों से अधिक जनविश्वास से अर्जित होती है, जिससे कि उनकी पार्टी अभी दूर चली गई है।

एक नजर

सारण के अमनौर में 115.930 किग्रा गांजा के साथ दो आरोपित गिरफ्तार



सारण,एजेंसी। अमनौर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उजले रंग की एक कार से 115.930 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उजले रंग की कार से अवैध गांजा सोन्हो के रास्ते अमनौर की ओर लाया जा रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद दंडाधिकारी की उपस्थिति में पुलिस टीम ने अमनौर चौक के समीप सघन वाहन जांच अभियान शुरू किया। इसी दौरान शाम करीब 4:35 बजे सोन्हो की ओर से आती एक उजली कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक वाहन भगाकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार को रोक लिया। पकड़े गए चालक की पहचान ग्राम राजवाड़ा, थाना घोड़ासहन, जिला पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) निवासी अशर्फी गिरी के पुत्र मोतीलाल गिरी के रूप में हुई। कार की तलाशी लेने पर 115.930 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में मोतीलाल गिरी ने बताया कि वह यह गांजा अमनौर थाना क्षेत्र के झखरी गांव निवासी मुकेश कुमार, पिता वन्धन राय, को डिलीवरी करने जा रहा था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने झखरी स्थित मुकेश कुमार के घर छापेमारी कर उसे भी गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में गांजे के अलावा एक कार, दो मोबाइल, 2900 रुपये नकद, एक आधार कार्ड, वाहन का स्मार्ट कार्ड और एक ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया गया है। अमनौर थाना ने एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

लाखों की नकदी, जेवरात और एक क्विंटल मखाना बरामद, एसआईटी की छापेमारी में 5 शातिर चोर चढ़े पुलिस के हत्थे



कटिहार,एजेंसी। जिले में गृहभेदन (घर में चोरी) की घटनाओं पर नकेल कसते हुए कटिहार पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। एसडीपीओ सदर-02 के नेतृत्व में गठित विशेष छापामारी टीम (एसआईटी) ने कुर्सेला थाना के एक तथा कोढ़ा थाना के पांच चोरी के मामलों का उद्भेदन करते हुए पांच शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 लाख 63 हजार 750 रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण, दो मोटरसाइकिल, सात मोबाइल फोन, एक क्विंटल मखाना और दो पलंग सहित चोरी का अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कांडों की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया था। टीम ने वैज्ञानिक अनुसंधान, सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन और मानवीय सूचना के आधार पर छापेमारी कर कुर्सेला थाना कांड संख्या 490/26 तथा कोढ़ा थाना कांड संख्या 363/26, 393/26, 419/26, 445/26, 472/26 एवं 473/26 में संलिप्त इन अपराधियों को दबोचा। गिरफ्तार अभियुक्तों में बरारी थाना क्षेत्र के बरारी ठाकुर पट्टी निवासी कुंदन कुमार (22 वर्ष), बड़ी भैंसदिरा निवासी मनोज मंडल (26 वर्ष), कोढ़ा थाना के नंदग्राम जरलाही निवासी कुंदन कुमार (26 वर्ष) तथा पोठिया थाना क्षेत्र के पोठिया सबदा नवटोलिया निवासी प्रिंस कुमार मंडल (25 वर्ष) और भंगहा निवासी सुदीश कुमार चौधरी (26 वर्ष) शामिल हैं। बरामद आभूषणों में चांदी की 22 अंगूठी व बिछिया, 5 जोड़ा पायल, एक जोड़ा बच्चे का मठिया, सोने की 5 नोजपिन और 2 कानबाली शामिल हैं। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

21 हजार दीपों से जगमगाएगा सौरा नदी तट, पहली बार दोनों किनारों पर होगी भव्य महाआरती



पूर्णिया। आगामी 24 नवंबर को देव दीपावली के अवसर पर पूर्णिया का ऐतिहासिक सौरा नदी तट आस्था, भक्ति और सनातन संस्कृति के अद्भुत संगम का साक्षी बनेगा। श्री राम सेवा संघ परिवार के तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव में पहली बार नदी के दोनों तटों पर भव्य महाआरती होगी। एक साथ 21 हजार दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और 17 महाआरतियों का विशेष संगम देखने को मिलेगा। आयोजन की तैयारियों की जानकारी देते हुए श्री राम सेवा संघ के संस्थापक राणा प्रताप सिंह, आतिश सनातनी एवं अन्य आयोजकों ने बताया कि प्रसिद्ध कलाकार गुल्लू दा के नेतृत्व में लगभग एक हजार कलाकार दस क्विंटल अबीर-गुलाल से विशाल रंगोली तैयार करेंगे। तिवारी बाबा जी महाराज के विशेष प्रयासों से वाराणसी के अस्सी घाट की प्रसिद्ध आरती टीम शामिल होगी। मिथिला के कलाकार भजन संध्या प्रस्तुत करेंगे, जबकि भागलपुर की विशेषज्ञ टीम आकर्षक आतिशबाजी करेगी। पूरे आयोजन स्थल को भगवा पताकाओं और भगवा लड़ियों से सजाया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि कोसी क्षेत्र के आठ जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालुओं को शुद्ध घी में भुना हुआ प्रसिद्ध मखाना प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। पार्किंग की व्यापक व्यवस्था की गई है। एक हजार से अधिक स्वयंसेवक व्यवस्था संभालेंगे। श्री राम सेवा संघ परिवार का एक-एक सदस्य पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ तैयारियों में जुटा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वैशाली में जनसभा की तैयारी पूरी, 20 लाख वर्गफीट में बना सभा स्थल

पटना,एजेंसी। बिहार के वैशाली जिले के जंदाहा-राजापाकर-महुआ औद्योगिक क्षेत्र (जाफरपट्टी) में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 21 नवंबर को होने वाली जनसभा को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। कार्यक्रम में लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए सभा स्थल, यातायात, पार्किंग, पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान नीतीश सेतु सहित कई परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे।

बिहार सरकार के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री का 21 नवंबर को दोपहर 1:20 बजे वैशाली जिले के रुस्तमपुर पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके बाद मुख्य कार्यक्रम जंदाहा-राजापाकर-महुआ औद्योगिक क्षेत्र, जाफरपट्टी में होगा। प्रधानमंत्री के अपराह्न 3:15 बजे जाफरपट्टी से प्रस्थान करने का कार्यक्रम है। वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियों की लगातार समीक्षा और निगरानी कर रहा है। सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, अग्निशमन, बिजली और पार्किंग सहित सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जंदाहा-राजापाकर-महुआ औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास और नीतीश सेतु का उद्घाटन कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण होंगे। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास और आधारभूत संरचना को नई



गति मिलने की उम्मीद है। मुख्य कार्यक्रम स्थल जाफरपट्टी पंचायत में करीब 20 लाख वर्गफीट क्षेत्र में विशाल सभा स्थल विकसित किया गया है। यहां भव्य मंच बनाया गया है। संभावित भीड़ को देखते हुए सभा स्थल के अलग-अलग हिस्सों में कार्यक्रम का सीधा दृश्य उपलब्ध कराने के लिए 60 एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं।

कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के तहत 32 पेयजल टैंक, 17 बोरिंग और 180 रनिंग वाटर टैप लगाए गए हैं। इसके अलावा दर्शकों के बैठने वाले स्थानों पर 140 वाटर डिस्पेंसर लगाए जाएंगे। स्वच्छता और जनसुविधा के लिए कुल 540 शौचालयों की व्यवस्था की गई है। इनमें मुख्य कार्यक्रम स्थल पर 300 शौचालय हैं, जिनमें 150 पुरुषों और 150 महिलाओं के लिए निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त पार्किंग और अन्य स्थानों पर 240 शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 27 मेडिकल कैंप बनाए गए हैं। साथ ही, विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर 25 एंबुलेंस तैनात रहेंगी, ताकि आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके। पटना और जहानाबाद से आने वाले वाहनों के लिए गांधी सेतु, पासवान चौक, अंडरपास, एनएच-322, हनुमान चौक, बिदुपुर, चकसिकंदर और बनारसी चौक होते हुए पार्किंग क्षेत्र एफ तक का मार्ग निर्धारित किया गया है। इसकी लंबाई करीब 19 किलोमीटर है। पटना और नालंदा से आने वाले वाहन कच्ची दरगाह सिक्स लेन पुल से बनारसी चौक पहुंचेंगे और वहां से पार्किंग क्षेत्र एफ तक जा सकेंगे। यह दूरी करीब 16 किलोमीटर है। पटना और सारण से आने वाले वाहनों को जेपी सेतु या गंडक पुल, रामाशीष चौक, महुआ मोड़, महुआ-ताजपुर रोड, हनुमान होटल, बाईपास, हरपुर चौक और बहसी चौक होते हुए पार्किंग क्षेत्र ई तक भेजा जाएगा। इस मार्ग की लंबाई करीब 34.5 किलोमीटर है। मुजफ्फरपुर से आने वाले वाहनों के लिए दो मार्ग निर्धारित किए गए हैं। पहला मार्ग एनएच-22, महुआ मोड़, हनुमान होटल, बाईपास, हरपुर चौक और बहसी चौक होते हुए पार्किंग क्षेत्र ई तक जाएगा। इसकी लंबाई करीब 78.5 किलोमीटर है। दूसरा वैकल्पिक मार्ग कांटी, महुआ बाजार, गांधी चौक, कुशहर चौक, बाईपास, हरपुर चौक और बहसी चौक होते हुए पार्किंग क्षेत्र ई तक पहुंचेगा। इसकी दूरी करीब 51.5 किलोमीटर है। समस्तीपुर से आने वाले वाहन भी दो मार्गों में से किसी एक का इस्तेमाल कर पार्किंग क्षेत्र ई तक पहुंच सकेंगे। पहला मार्ग ताजपुर-महुआ रोड, एनएच-49, ताजपुर बाईपास, कुशहर चौक, हरपुर चौक और बहसी चौक से होकर गुजरेगा।

पीएम मोदी कल सुपौल को देंगे विकास परियोजनाओं की सौगात, 126 करोड़ की डेयरी योजनाओं का होगा शिलान्यास

सुपौल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार, 21 नवंबर को सुपौल जिले को विकास योजनाओं की कई महत्वपूर्ण सौगात देंगे। प्रधानमंत्री के कर-कमलों द्वारा विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया जाएगा। इस अवसर पर जिले से संबंधित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सुपौल नगर भवन (टाउन हॉल) में आयोजित होगा। जिला प्रशासन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस अवसर पर सड़क, डेयरी विकास और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा। इन योजनाओं से जिले में आधारभूत संरचना के विकास के साथ-साथ आवागमन, रोजगार और शिक्षा की सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 327ष्ठ पर सरायगढ़ से लालगंज-गणपतगंज होते हुए राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 106 (नवीन एनएच-131) तक सड़क परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा। करीब 10.672 किलोमीटर लंबी इस सड़क का दो लेन सहित पेव्ड शोल्डर के साथ उन्नयन एवं निर्माण कराया गया है। इसके शुरू होने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा तथा सड़क संपर्क और यातायात व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। डेयरी विकास के क्षेत्र में भी जिले को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार तथा बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (कॉम्फेड) के अंतर्गत कोसी दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ, सुपौल में कुल 126.07 करोड़ रुपये की विभिन्न डेयरी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ाने के साथ सहकारी डेयरी व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। इससे जिले के पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। शिक्षा के क्षेत्र में सुपौल प्रखंड की हरदी पंचायत के देवेन्द्रनगर, चौघारा स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत निर्मित इस विद्यालय भवन की क्षमता 720 विद्यार्थियों की है। इसके निर्माण पर 4607.97 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। विद्यालय के शुरू होने से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

किराये पर चल रहे 2018 आंगनबाड़ी केंद्र होंगे सरकारी भवनों में शिफ्ट, पोषण ट्रैकर में प्रथम रैंक पर डीएम ने दी बधाई

कटिहार। कटिहार में किराये के कमरों में संचालित हो रहे 2018 आंगनबाड़ी केंद्रों को अब जल्द ही सरकारी भवनों की छत नसीब होगी। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने शुक्रवार को एनआईसी सभागार में आयोजित आईसीडीएस की समीक्षात्मक बैठक में इन सभी केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से सरकारी स्कूलों या भवनों में स्थानांतरित करने की रूपरेखा तय की। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि भवनहीन केंद्रों के लिए अविलंब भूमि चिह्नित कर एनओसी प्राप्त की जाए, जबकि जर्जर केंद्रों का कायाकल्प अभियान के तहत जीर्णोद्धार कर वहां बुनियादी सुविधाएं बहाल की जाएं।

बैठक के दौरान डीएम ने राज्य स्तर पर पोषण ट्रैकर की रैंकिंग में कटिहार जिला के प्रथम स्थान पर रहने पर संतोष व्यक्त किया और इसके लिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी सीडीपीओ, कर्मियों व आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं को बधाई दी। उन्होंने इस रैंक को बरकरार रखने के लिए सभी इंडिकेटर्स को शत-प्रतिशत पूरा करने तथा निम्न प्रदर्शन करने वाली परियोजनाओं को एक सप्ताह के भीतर सुधार लाने को कहा। निरीक्षण ऐप (आंगन ऐप) पर खराब प्रदर्शन करने वाली महिला पर्यवेक्षिकाओं से स्पष्टीकरण पूछकर कार्रवाई करने तथा टीएचआर व गर्म पका भोजन की एंट्री शत-प्रतिशत पोषण ट्रैकर पर दर्ज करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने विशेष अभियान चलाकर नाटापन, कुपोषित व अतिकुपोषित बच्चों की पहचान करने और गंभीर बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) भेजने का आदेश दिया। आभा व अपार आईडी की समीक्षा करते हुए सभी परियोजनाओं में बच्चों व महिलाओं के आधार कार्ड बनाने के लिए विशेष कैंप लगाने को कहा गया। वहीं, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में लक्ष्य के अनुरूप कम उपलब्धि पर खेद जताते हुए डीएम ने स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर नवंबर के अंतिम सप्ताह तक शत-प्रतिशत सुधार लाने की सख्त हिदायत दी। बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, डीपीओ मनरेगा, कार्यपालक अभियंता एलएईओ (कटिहार व बारसोई), सभी सीडीपीओ तथा वीसी के माध्यम से सभी बीडीओ व सीओ शामिल हुए।

गोवा फिल्म फेस्टिवल में बिहार में शूट हुई फिल्म ऑफलाइन की होगी स्पेशल स्क्रीनिंग

गोवा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (आईएफएफआई) के 57वें संस्करण का आगाज गोवा में हुआ। इस मौके पर वेव्स फिल्म बाजार में बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम की ओर से बिहार पवेलियन स्थापित किया गया है। पवेलियन में फिल्म निर्माता और फिल्म जगत से जुड़े लोगों ने फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024, बिहार के शूटिंग लोकेशन, अनुदान एवं शूटिंग अनुमति की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ ही अधिकारियों के समक्ष अपनी अपेक्षाओं को रखा। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन(इंपा) के अध्यक्ष अभय सिन्हा के साथ बिहार पवेलियन पहुंचे कई फिल्म निर्माताओं का स्वागत बिहार फिल्म निगम के परामर्शी (फिल्म) प्रो. अरविंद रंजन दास ने किया।

बिहार पवेलियन पहुंचे फिल्म गदर के निर्माता कमल मुकुट ने बिहार सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, फिल्म प्रोत्साहन नीति लागू होने से कलाकारों को काम मिलेगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी को सिनेमा कल्चर से जोड़ने की जरूरत है, जिसकी शुरुआत बिहार के गोपालगंज जिले से हो रही है, जहां 99 रुपये में आम जनता नई फिल्मों का आनंद बड़े पर्दे पर उठा सकती है। वह इसकी विस्तृत रूपरेखा फिल्म निगम के प्रबंध निदेशक प्रणव कुमार के समक्ष रखेंगे। बिहार में शूट हुई हिंदी फिल्म ऑफलाइन के लेखक-निर्देशक नवीन चंद्र गणेश ने कहा कि आईएफएफआई फिल्म



लैब में फिल्म वितरकों के समक्ष फिल्म की स्क्रीनिंग होनी है। उन्होंने कहा कि शूटिंग अनुमति की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और उन्हें अनुमति लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिल्म प्रोड्यूसर साक्षी ने प्रबंध निदेशक प्रणव कुमार का धन्यवाद देते हुए कहा, 'मुझे इस बात पर खुशी है कि बिहार में फिल्म प्रोड्यूसर को शूटिंग की अनुमति ऑनलाइन मिलने के साथ ही भरपूर वित्तीय और प्रशासनिक सहयोग मिल रहा है।' उन्होंने कहा कि उनकी अगली फिल्म की शूटिंग बिहार में होगी, जिसकी कहानी बिहार से ही जुड़ी है। आईएफएफआई का आयोजन 20 से 28 नवंबर तक गोवा के विभिन्न स्थानों पर हो रहा है। इस दौरान फिल्म बाजार के आयोजन के साथ ही फिल्म स्क्रीनिंग, वर्कशॉप, पैनल डिस्कशन में शामिल होने के लिए देश-विदेश से फिल्म जगत से जुड़े लोग गोवा पहुंच रहे हैं। गोवा फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने गई चार सदस्यीय टीम में बिहार फिल्म निगम के परामर्शी(फिल्म) प्रो. अरविंद रंजन दास, कनीय परामर्शी(संचार) कुमार गौरव एवं सोशल मीडिया मैनेजर अनुभव सागर शामिल हैं।

एक साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच पहुंचे विधायक आनंद मिश्रा, विकास कार्यों का दिया हिसाब

बक्सर,एजेंसी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर बक्सर सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक आनंद मिश्रा ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत किया। जासो रोड स्थित कमल सेवा केंद्र के विधायक कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने एक वर्ष के दौरान किए गए प्रयासों, विकास योजनाओं, उपलब्धियों और आगामी प्राथमिकताओं की जानकारी दी। इस मौके पर राजग के जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश भुवन (भाजपा), ऋषि राय (हम), राजकुमार शर्मा (जदयू), विंध्याचल सिंह कुशवाहा (रालोमो) तथा भाजपा जिला मीडिया प्रभारी उमाशंकर राय मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता में विधायक आनंद मिश्रा ने कहा कि 14 नवंबर 2025 को जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें विधानसभा पहुंचाया, वह उनके लिए सम्मान के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि विकास और जवाबदेही उनकी कार्यशैली के दो प्रमुख आधार हैं। चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे के अनुरूप उन्होंने अपने कार्यों का हिसाब सार्वजनिक किया है, ताकि लोग जान सकें कि कौन से काम पूरे हुए, किन पर प्रगति हो रही है और किन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास जारी हैं।

विधायक ने अपने कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि बक्सर में 23 वर्षों से लंबित



केंद्रीय विद्यालय के भूमि विवाद के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वहीं, केंद्रीय कारा परिसर में स्थित भगवान वामन के प्राचीन मंदिर को जेल परिसर से अलग कर श्रद्धालुओं के लिए स्वतंत्र रास्ता और सीमा दीवार उपलब्ध कराने की पहल को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। उन्होंने इसे धार्मिक आस्था और जनसुविधा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इसके अलावा रेल ओवरब्रिज निर्माण, एक्सप्रेसवे से जुड़ाव, गंगा पुल परियोजना और आधुनिक सीवरेज व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विषयों पर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बक्सर की समस्याओं और क्षेत्र की जरूरतों को विधानसभा में मजबूती से उठाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। जनता के प्रति पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विधायक कार्यालय की ओर से AnandMishra.org डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इसके माध्यम से लोग मोबाइल पर ही विधानसभा में उठाए गए मुद्दों, जनसंवाद कार्यक्रमों, शिकायतों, बिजली समस्याओं, ग्रामीण सड़क योजनाओं, भगवान वामन मंदिर से जुड़े प्रयासों और विधायक निधि से अनुशंसित योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विधायक ने कहा कि एक वर्ष में सभी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। कुछ कार्य पूरे हुए हैं, जबकि कई योजनाओं पर काम जारी है। आने वाले वर्ष में विकास कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि जनता को उनसे सवाल पूछने और काम का हिसाब मांगने का पूरा अधिकार है।

भागलपुर में पुलिस का 'ऑपरेशन प्रहार' : 7 विशेष टीमों का गठन, संवेदनशील हॉटस्पॉट्स पर कड़ा पहरा

भागलपुर,एजेंसी। शहर में विधि-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और बढ़ती आपराधिक वारदातों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए भागलपुर पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्र में एक व्यापक और विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस मुहिम के तहत ज्वेलरी दुकानों में होने वाली चोरी, बाइक चोरी, चेन छिनतई और अन्य स्ट्रीट क्राइम को जड़ से खत्म करने के लिए कुल सात विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है, जिन्हें अलग-अलग क्षेत्रों और अपराध की श्रेणियों के अनुसार विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पुलिस प्रशासन ने पिछले कुछ समय में हुई आपराधिक घटनाओं का विश्लेषण कर शहर के प्रमुख बाजारों, सर्राफा मंडियों, बैंक-एटीएम परिसरों, रेलवे स्टेशन के बाहरी इलाकों और भीड़भाड़ वाले चौक-चौराहों को 'हॉटस्पॉट' और संवेदनशील स्थानों के रूप में चिह्नित किया है। इन स्थानों पर चिह्नित पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों की विशेष प्रतिनियुक्ति की गई है।

इसके अतिरिक्त, असामाजिक तत्वों और झपटमारों की पहचान करने के लिए भीड़भाड़ वाले इलाकों में सादे लिबास में भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जो संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रख रहे हैं। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए शहरी क्षेत्र के सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस द्वारा सुबह की गश्ती से लेकर देर रात तक सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। प्रमुख प्रवेश और निकास मार्गों



पर दोपहिया व चारपहिया वाहनों के दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। साथ ही, हाल के दिनों में जेल से छूटे अपराधियों और पुराने हिस्ट्रीशीटरों की गतिविधियों का भी सत्यापन किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इन सात विशेष टीमों को जिला आसूचना इकाई और तकनीकी सेल के साथ जोड़ा गया है। शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए संदिग्धों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी वारदात के होने से पहले ही अपराधियों को दबोचा जा सके या घटना होने की स्थिति में त्वरित उद्भेदन सुनिश्चित हो सके। पुलिस की इस सक्रियता से स्थानीय सर्राफा व्यवसायी और आम नागरिकों ने राहत की सांस ली है।

एक नजर

कौशाम्बी के दो क्रिकेट सितारों का भव्य सम्मान, 22.25 लाख में हुआ चयन



कौशांबी,एजेंसी। राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करने वाले क्रिकेट खिलाड़ी लविश कौशल और जैद खान को शुक्रवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम कौशाम्बी में सम्मानित किया गया। दोनों खिलाड़ियों का चयन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (आईएसपीएल) के चौथे सीजन में हुआ है। नीलामी में लविश को 17 लाख और जैद को 5.25 लाख रुपये में टीमों ने खरीदा। दोनों खिलाड़ियों पर कुल 22.25 लाख रुपये की बोली लगी थी। लविश कौशल को अभिनेता अक्षय कुमार की फ्रेंचाइजी श्रीनगर के वीर ने, जबकि जैद खान को अभिनेता ऋतिक रोशन की फ्रेंचाइजी बेंगलुरु स्ट्राइकर्स ने अपनी टीम में शामिल किया है। सम्मान समारोह में क्रिकेट कोच कौशिक पाल ने युवा खिलाड़ियों को खेल की बारीकियां, तकनीक और अनुशासन के महत्व की जानकारी दी। लविश कौशल ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि कामयाबी के लिए वर्षों तक मेहनत करनी पड़ती है। युवाओं को लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। वहीं, जैद खान ने चोट के कारण अपने क्रिकेट सफर में आई चुनौतियों का जिक्र करते हुए खिलाड़ियों को फिटनेस और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने अनुशासन और नियमित अभ्यास को सफलता की कुंजी बताया। इस दौरान कोच संदीप ने बच्चों को मिठाई और फल वितरित किए। कार्यक्रम के अंत में ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉ. अरुण केशरवानी ने सभी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर की लीग में चयन पूरे जिले के लिए गौरव की बात है। ऐसे आयोजन से जिले की छिपी खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में आईसीसी आचार संहिता उल्लंघन के दोषी पाए गए तौहिद हृदोय



दुबई,एजेंसी। बांग्लादेश के बल्लेबाज तौहिद हृदोय को जोहानिसबर्ग के वांडरर्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता के स्तर-1 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। इस उल्लंघन के लिए हृदोय पर मैच फीस का 40 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है और उनके खाते में दो डिमेरिट अंक भी जोड़े गए हैं। उन्होंने आईसीसी खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.8 का उल्लंघन किया, जो अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर असहमति जताने से संबंधित है। यह घटना बुधवार को उस समय हुई, जब खराब रोशनी के कारण खेल रोक दिया गया था। इसके बाद मैदानी अंपायर अहसान रजा और एलेक्स व्हार्फ बांग्लादेश टीम के ड्रेसिंग रूम की बालकनी के पास से गुजर रहे थे। बांग्लादेशी बल्लेबाज ने खेल पहले नहीं रोकने के अंपायरों के फैसले की आलोचना की। आईसीसी के अनुसार, अंपायरों से बात करने का उनका तरीका आक्रामक और अनुचित था। हृदोय ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और आईसीसी के एलीट पैनल के मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की ओर से प्रस्तावित सजा भी स्वीकार कर ली। इसलिए इस मामले में औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। हृदोय के खिलाफ आरोप मैदानी अंपायर अहसान रजा और एलेक्स व्हार्फ, तीसरे अंपायर आसिफ याकूब तथा चौथे अंपायर लुबाबालो गकुमा ने लगाए थे। 24 महीने की अवधि में यह हृदोय का पहला अपराध है। आचार संहिता के स्तर-1 के उल्लंघन पर खिलाड़ी को न्यूनतम आधिकारिक चेतावनी दी जा सकती है। वहीं, अधिकतम सजा के तौर पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना और एक या दो डिमेरिट अंक दिए जा सकते हैं। इस बीच, दक्षिण अफ्रीका ने गुरुवार को दूसरी पारी में नौ विकेट शेष रहते 12 रन का मामूली लक्ष्य हासिल कर टेस्ट मैच जीत लिया। इसके साथ ही उसने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली। पहली पारी में 157 रन से पिछड़ने के बाद बांग्लादेश की टीम दूसरी पारी में भी संघर्ष करती नजर आई और महज 168 रन पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में अपना सलामी बल्लेबाज मार्क्स एकरमैन पहले ही ओवर में गंवा दिया, लेकिन दूसरे ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भी पहले स्थान पर पहुंच गया।

गौतम गंभीर के संदेश और समर्थन ने चोट से वापसी के दौरान बढ़ाया हौसला : आकाशदीप

वेलिंगटन,एजेंसी। भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप ने पीठ की चोट से उबरकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के दौरान मुख्य कोच गौतम गंभीर से मिले समर्थन को अपनी प्रेरणा का बड़ा स्रोत बताया है। उन्होंने कहा कि चोट के समय गंभीर लगातार उनसे संपर्क करते थे, उनके पुनर्वास की जानकारी लेते थे और पहले से अधिक मजबूत होकर वापसी करने के लिए प्रेरित करते थे। एक साल से अधिक समय बाद टेस्ट क्रिकेट में लौटे आकाशदीप ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पहली गेंदबाजी पारी में तीन विकेट लिए। उनकी वापसी ऐसे समय हुई है, जब वह घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट श्रृंखलाओं में नहीं खेल पाए थे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था। आकाश ने पिछले साल जुलाई में ओवल टेस्ट के बाद पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेला है। वापसी से पहले उन्होंने लिंकन में भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच दो अनौपचारिक टेस्ट मुकाबले खेले थे, जिनमें तीन विकेट लेने के साथ एक अर्धशतक भी लगाया था। इसके अलावा बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी के छह मैचों में 22 विकेट लिए, जिसमें एक पारी में पांच विकेट भी शामिल थे। जम्मू-कश्मीर के खिलाफ शेष भारत की दलीप ट्रॉफी जीत में भी उन्होंने दोनों पारियों में तीन-तीन विकेट लेकर कुल छह विकेट हासिल किए थे। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में आकाशदीप ने पीठ की चोट के बाद वापसी की चुनौतियों और गंभीर से मिले सहयोग के बारे में बताया।

वेलिंगटन टेस्ट दूसरा दिनः जायसवाल-राहुल ने भारत को दिलाई मजबूत शुरुआत, 1 विकेट पर बनाए 159 रन

वेलिंगटन,एजेंसी। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के बीच हुई 130 रन की शानदार साझेदारी की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मजबूत शुरुआत की है। न्यूजीलैंड की पहली पारी के 368 रन के जवाब में भारतीय टीम ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में एक विकेट के नुकसान पर 159 रन बना लिए हैं। इस तरह भारत अब न्यूजीलैंड से 209 रन पीछे है, जबकि उसके नौ विकेट सुरक्षित हैं। दिन का खेल समाप्त होने पर केएल राहुल 52 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि देवदत्त पडिक्कल 15 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 85 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। उन्होंने 89 गेंदों का सामना किया और 16 चौके लगाए। हालांकि, वह अपना शतक पूरा करने से चूक गए। दूसरी ओर, राहुल ने संयम और आक्रामकता का अच्छा संतुलन बनाते हुए नाबाद अर्धशतक पूरा किया। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को शानदार शुरुआत दिलाई और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाया।

न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रन पर समाप्त होने के बाद भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने सावधानी के साथ पारी की शुरुआत की। भारत ने दूसरे दिन के अंतिम सत्र में अपनी पारी आगे बढ़ाई। उस समय टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 16 रन था। जायसवाल 11 और राहुल पांच रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। शुरुआती ओवरों में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी और काइल जैमीसन ने अपनी सटीक लाइन-लेंथ और उछाल से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश की। भारतीय सलामी जोड़ी ने हालांकि धैर्य बनाए रखा और धीरे-धीरे रन गति बढ़ानी शुरू की। जायसवाल ने हेनरी की गेंदों पर दो



चौके लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए, जबकि राहुल ने जैकब डफी के खिलाफ आकर्षक शॉट लगाकर रन बटोरे। भारत ने 13.4 ओवर में 50 रन पूरे किए। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। शुरुआती 10 ओवर में भारत ने 23 रन बनाए थे, लेकिन अगले 10 ओवर में 56 रन जोड़कर अपनी रन गति में उल्लेखनीय सुधार किया। 20 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 79 रन था। उस समय जायसवाल 43 और राहुल 34 रन बनाकर खेल रहे थे।

जायसवाल ने जैकब डफी के 22वें ओवर में तीन शानदार चौके लगाए। इनमें उनका स्ट्रेट ड्राइव विशेष रूप से आकर्षक रहा। उन्होंने 66 गेंदों में आठ चौकों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद नाथन स्मिथ की गेंद पर चौका लगाकर भारत ने 23.4 ओवर में 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया। जायसवाल ने इसके बाद आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और विकेटकीपर के ऊपर से शानदार रैंप शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया। हालांकि, उनकी शानदार पारी का अंत मैट हेनरी ने किया। हेनरी की गेंद पर जायसवाल ने विकेट के पीछे टॉम ब्लंडेल को कैच थमा दिया। न्यूजीलैंड ने रिव्यू लिया, जिसमें फैसला गेंदबाज के पक्ष में गया। इस तरह भारत को 27.5 ओवर में 130 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। जायसवाल 85 गेंदों में 85 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 16 चौके शामिल रहे। पहला विकेट गिरने के बाद केएल राहुल ने देवदत्त पडिक्कल के साथ पारी को आगे बढ़ाया। राहुल ने जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। दोनों ने दिन के शेष ओवरों में कोई और विकेट नहीं गिरने दिया। भारत ने 37वें ओवर में 150 रन पूरे किए और दिन का खेल समाप्त होने तक अपना स्कोर एक विकेट पर 159 रन पहुंचा दिया। इससे पहले न्यूजीलैंड ने हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स के शानदार शतकों की बदौलत अपनी पहली पारी में 368 रन बनाए। भारतीय तेज गेंदबाजों ने मैच की शुरुआत में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को महज 70 रन पर पांच झटके देकर मुश्किल में डाल दिया था। हालांकि, इसके बाद निकोल्स और फिलिप्स ने छठे विकेट के लिए 216 रन की बेहतरीन साझेदारी कर टीम को संकट से बाहर निकाल दिया। दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने अपनी पारी छह विकेट पर 317 रन से आगे बढ़ाई। हेनरी निकोल्स 146 और नाथन स्मिथ 13 रन बनाकर नाबाद थे। दिन के शुरुआती सत्र में निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों के सामने मजबूती से बल्लेबाजी की। फिलिप्स ने 216 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 118 रन बनाए। यह भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में उनका पहला शतक था। आकाश दीप ने 94वें ओवर में फिलिप्स को 286 रन के स्कोर पर आउट कर भारत को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। इसके साथ ही निकोल्स के साथ उनकी 216 रन की साझेदारी समाप्त हुई। फिलिप्स के आउट होने के बाद भी निकोल्स ने एक छोर संभाले रखा और अपनी शानदार पारी जारी रखी। निकोल्स ने दूसरे दिन की शुरुआत 113 रन से की थी। उन्होंने सुबह के सत्र में 33 रन जोड़कर अपना स्कोर 146 तक पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने 175 गेंदों में 150 रन पूरे किए। दूसरे सत्र में भी उन्होंने अपनी बल्लेबाजी जारी रखी और नाबाद 175 रन बनाकर पवेलियन लौटे बिना न्यूजीलैंड की पारी का अंत देखा। उनकी 335 गेंदों की पारी में 21 चौके शामिल रहे। यह उनके टेस्ट करियर का 12वां शतक भी रहा।

भारत में 100 ग्रैंडमास्टर बनने और शतरंज की बढ़ती लोकप्रियता से दिव्या, विदित उत्साहित

नई दिल्ली। अर्जुन पुरस्कार विजेता और शतरंज ग्रैंडमास्टर दिव्या देशमुख तथा विदित गुजराती भारत में शतरंज की हालिया प्रगति से काफी उत्साहित हैं। खासतौर पर इस महीने की शुरुआत में देश के 100 ग्रैंडमास्टर बनने की उपलब्धि को उन्होंने भारतीय शतरंज के लिए महत्वपूर्ण बताया। अनुज श्रीवास्त्री ने 8 नवंबर 2026 को फिलीपींस में आयोजित सातवीं आसियान प्लस व्यक्तिगत ओपन शतरंज चैंपियनशिप जीतकर भारत के 100वें ग्रैंडमास्टर बनने का गौरव हासिल किया। मध्य प्रदेश के 22 वर्षीय अनुज राज्य के पहले ग्रैंडमास्टर भी बने।

दिव्या ने भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) मीडिया से बातचीत में कहा, 'मुझे लगता है कि यह सराहनीय उपलब्धि है कि हमने अपना 100वां ग्रैंडमास्टर बना लिया है और यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस बारे में ट्वीट किया। यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि शतरंज को इतनी पहचान और लोकप्रियता मिल रही है तथा लोग इसे पहले से कहीं अधिक खेलने लगे हैं। इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि हमने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे अंदर आगे कई सौ और हजार ग्रैंडमास्टर बनाने की क्षमता है। कई बच्चे शतरंज में आगे आ रहे हैं और उन्हें यह खेल पसंद है। व्यक्तिगत रूप से यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है।' भारत के 100 शतरंज ग्रैंडमास्टर बनने का सफर विश्वनाथन आनंद से शुरू हुआ था। आनंद 1988 में देश के पहले ग्रैंडमास्टर बने थे। वह आगे चलकर पांच बार विश्व चैंपियन बने। उनके बाद 1991 में दिव्येंदु बरुआ और 1997 में प्रवीण थिप्से ग्रैंडमास्टर बने।

पिछले कुछ दशकों में देश में शतरंज के तेजी से हुए विकास पर विदित ने कहा, 'मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों से शतरंज लगातार आगे बढ़ रहा है। इसका अहसास हमें तब हुआ, जब हमने 2024 फिडे ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता। 100 वर्षों में यह पहली बार था, जब हम ऐसा करने में सफल रहे। इसके अलावा मौजूदा विश्व चैंपियन भी भारतीय हैं और वह गुकेश हैं। उन्होंने कहा, 'भारत में शतरंज का विकास हो रहा है और इस खेल की वजह से दुनिया भर में भारत को बहुत सम्मान मिल रहा है। हमने जिस तरह से यह खेल खेला है, उससे हमारी पहचान मजबूत हुई है। हम दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक हैं। अगर हम किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं तो भारत को खिताब का प्रबल दावेदार माना जाता है।

तिलक और कुशाग्र के शतकों के बाद हर्षित-प्रिंस का कहर, भारत 'ए' ने नेपाल को 306 रन से हराया

दोहा,एजेंसी। कप्तान तिलक वर्मा और कुमार कुशाग्र के शानदार शतकों के बाद तेज गेंदबाजों हर्षित राणा और प्रिंस यादव की घातक गेंदबाजी के दम पर भारत 'ए' ने एसीसी पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स के ग्रुप-बी मुकाबले में नेपाल को 306 रन से हरा दिया। भारत 'ए' ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में नौ विकेट पर 332 रन बनाए। जवाब में नेपाल की टीम 11.3 ओवर में महज 26 रन पर सिमट गई। नेपाल का 26 रन का स्कोर लिस्ट-ए क्रिकेट के इतिहास का पांचवां सबसे कम टीम स्कोर है। इस सूची में सबसे कम स्कोर का अनचाहा रिकॉर्ड वेस्टइंडीज अंडर-19 के नाम है।

टीम 17 अक्टूबर 2007 को ब्लेयरमोंट में बारबाडोस के खिलाफ मुकाबले में 14.3 ओवर में महज 18 रन पर ऑलआउट हो गई थी। लिस्ट-ए क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम स्कोर का अनचाहा रिकॉर्ड वेस्टइंडीज अंडर-19 के नाम है। टीम 17 अक्टूबर 2007 को ब्लेयरमोंट में बारबाडोस के खिलाफ 14.3 ओवर में महज 18 रन पर ऑलआउट हो गई थी। इस सूची में दूसरे स्थान पर सारासेंस स्पोर्ट्स क्लब है, जिसने 13 दिसंबर 2012 को कोलंबो में कोल्ट्स क्रिकेट क्लब के खिलाफ 19 रन बनाए थे। तीसरे स्थान पर मिडलसेक्स की टीम है, जो 23 जून 1974 को लीड्स में यॉर्कशायर के खिलाफ 23 रन पर सिमट गई थी। चौथे स्थान पर ओमान की टीम है, जिसने 19 फरवरी 2019 को अल अमीरात में स्कॉटलैंड के खिलाफ 24 रन बनाए थे। अब 20 नवंबर 2026 को दोहा में भारत 'ए' के खिलाफ 26 रन पर सिमटने वाली नेपाल की टीम इस सूची



में पांचवें स्थान पर आ गई है। आज के मैच में नेपाल की पारी को समेटने में हर्षित राणा और प्रिंस यादव की स्विंग और सीम गेंदबाजी ने अहम भूमिका निभाई। चोट से वापसी कर रहे हर्षित ने पहली ही गेंद से शानदार लय दिखाई और गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराया। नेपाल के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की इस बेहतरीन गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं दे सके। भारत 'ए' के कप्तान तिलक वर्मा ने 113 गेंदों पर 107 रन की पारी खेली। उन्होंने छह चौके और चार छक्के लगाए। वहीं, कुमार कुशाग्र ने 102 गेंदों पर 117 रन बनाए। उनकी पारी में 10 चौके और पांच छक्के शामिल रहे। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 191 गेंदों पर 206 रन की शानदार साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। भारत 'ए' की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अभिषेक शर्मा 13 गेंदों पर नौ रन बनाकर आउट हुए। आयुष बडोनी सात गेंदों पर दो रन ही बना सके, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों पर 26 रन बनाए। इसके बाद तिलक और कुशाग्र ने पारी को संभाला और बड़े स्कोर की नींव रखी। कुशाग्र के आउट होने के बाद तिलक ने भी तेजी से रन बनाए। रिंकू सिंह ने सात गेंदों पर नौ रन का योगदान दिया। सूर्यांश शेडगे ने 14 गेंदों पर नाबाद 36 रन की विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने चार छक्के और एक चौका लगाया। शाहबाज अहमद ने आठ रन बनाए। विप्रज निगम खाता नहीं खोल सके, जबकि हर्षित राणा ने एक रन बनाया। प्रिंस यादव एक रन बनाकर नाबाद रहे। नेपाल की ओर से ललित राजबंशी और संदीप लामिछाने ने तीन-तीन विकेट लिए। नंदन यादव ने दो और पवन सर्राफ ने एक विकेट हासिल किया।

बीएचयू में पूर्वी क्षेत्र अंतर-विश्वविद्यालय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज, पहले दिन 14 मुकाबले खेले गए

वाराणसी,एजेंसी। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के तत्वावधान में शुक्रवार को 'ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल टूर्नामेंट (महिला) 2026-27' का भव्य शुभारंभ हुआ। विश्वविद्यालय के एम्फीथिएटर ग्राउंड स्थित वॉलीबॉल कोर्ट में आयोजित प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि बीएचयू के रजिस्ट्रार राजन श्रीवास्तव ने वसंत महिला महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. अलका सिंह की उपस्थिति में किया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजन श्रीवास्तव ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें खेल भावना, अनुशासन और टीम भावना के साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रतियोगिता के आयोजन सचिव डॉ. रोबिन कुमार सिंह ने बताया कि टूर्नामेंट के लिए कुल 36 टीमों ने जनरल एंट्री कराई थी, जिनमें से 28 टीमों की डिटेल एंट्री प्राप्त हुई है। प्रतियोगिता में मेजबान काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अलावा रांची विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, कल्याणी विश्वविद्यालय, बर्दवान विश्वविद्यालय, कीट और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय समेत पूर्वी भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों की टीमें हिस्सा



ले रही हैं। यह प्रतियोगिता 24 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी।

विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद की उपाध्यक्ष प्रो. अर्चना सिंह ने अतिथियों, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, टीम प्रबंधकों एवं दर्शकों का स्वागत किया। वहीं, परिषद के महासचिव प्रो. ए.के. नेमा ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आयोजन से जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त आयोजन सचिव डॉ. प्रमोद कुमार यादव ने किया। प्रतियोगिता के पहले दिन कुल 14 मुकाबले खेले गए। इनमें बर्दवान विश्वविद्यालय ने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय को 3-0 से हराया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ को 3-0 से पराजित किया। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने नागालैंड विश्वविद्यालय को तथा उत्कल विश्वविद्यालय ने बीआरए बिहार विश्वविद्यालय को 3-0 से शिकस्त दी। इसी क्रम में कल्याणी विश्वविद्यालय ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, श्री स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय, शहीद एम.के. विश्वविद्यालय ने राजीव गांधी विश्वविद्यालय और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने मगध विश्वविद्यालय को 3-0 से पराजित किया। सीयूएसबी, गया ने रमा देवी विश्वविद्यालय को 3-0 से हराया, जबकि रेवेनशॉ विश्वविद्यालय ने महाराजा श्रीराम चंद्र भंज देव विश्वविद्यालय को इसी अंतर से शिकस्त दी। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय को 3-1 से पराजित किया। वहीं, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने एनएसयू, मणिपुर को 3-0 से हराया।

भारत में निर्माण करें, भारत में खेलें और भारत के साथ आगे बढ़ें', खेल उद्योग के दिग्गजों से बोले मांडविया

नई दिल्ली। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को नई दिल्ली में फिक्की (भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ) के खेल कारोबार पर वैश्विक शिखर सम्मेलन टर्फ के 16वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉ. मांडविया ने कहा, 'खेल युवाओं के विकास, सामाजिक समावेशन, आर्थिक अवसरों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरे हैं।

उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने खेलों को राष्ट्र निर्माण के अपने एजेंडे के केंद्र में रखा है। हमारा दृष्टिकोण एक स्पष्ट सोच से प्रेरित है- मैदान से पदक मंच तक हर उभरते खिलाड़ी के लिए अवसर तैयार करना। यह शिखर सम्मेलन 'भारत की खेल अर्थव्यवस्था को गति देना : साझेदारी, नवाचार और वैश्विक नेतृत्व' विषय पर आयोजित किया जा रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत के खेल तंत्र में आए बदलावों का उल्लेख करते हुए डॉ. मांडविया ने कहा, 'खेलो इंडिया मिशन, फिट इंडिया आंदोलन और टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना जैसी पहलों के माध्यम से हम जमीनी स्तर पर खेलों में भागीदारी बढ़ा रहे हैं, खेल प्रतिभाओं की पहचान कर रहे हैं और उच्च प्रदर्शन वाले खेलों तक पहुंचने के रास्ते तैयार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में नई खेलो इंडिया योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत अगले पांच वर्षों के लिए 36,441 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, प्रतिभाओं को निखारना और देशभर में खेलों के विकास को बढ़ावा देना है। भारत के खेल प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए डॉ. मांडविया ने कहा, 'एशियाई खेल 2026 में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा।'

उन्होंने कहा, 'एशियाई पैरा खेल 2026 में भी भारत का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा, जहां हमारे पैरा खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड 114 पदक जीते। इन खेलों में यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। खेल क्षेत्र में उद्योग जगत की भूमिका पर बोलते हुए डॉ. मांडविया ने कहा, 'हम मानते हैं कि खेलों का भविष्य केवल खिलाड़ियों और खेल संस्थानों से ही नहीं, बल्कि एक मजबूत, प्रतिस्पर्धी और नवाचार से प्रेरित खेल उद्योग से भी तय होगा। सरकार ने भारत को खेल सामग्री के निर्माण और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से खेलो इंडिया खेल सामग्री विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए 1,856.67 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। खेलो भारत नीति 2025 में भारत में खेलों के विकास के लिए व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, जबकि राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम खेल प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहा है। डॉ. मांडविया ने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करने की भारत की मंशा भी सामने रखी।

एक नजर

कर्स्टन ए. डेविस अमेरिका की राष्ट्रीय साइबर निदेशक नियुक्त



वाशिंगटन (अमेरिका)। व्हाइट हाउस ने कर्स्टन ए. डेविस को नया राष्ट्रीय साइबर निदेशक नियुक्त किया है। उन्होंने शॉन केर्नक्रॉस की जगह ली। हाल के दिनों में अमेरिका के हवाई यातायात, बैंकिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालियों में बड़े पैमाने पर आई तकनीकी रुकावटों के बाद प्रशासन को आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके बाद पूर्व साइबर प्रमुख शॉन केर्नक्रॉस को पद से हटाया गया। स्थायी रूप से इस पद पर नियुक्ति के लिए सीनेट की मंजूरी आवश्यक होती है। इस वजह से डेविस फिलहाल कार्यवाहक के रूप में ऑफिस ऑफ द नेशनल साइबर डायरेक्टर (ओएनसीडी) का नेतृत्व करेंगी। कर्स्टन डेविस अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) की मुख्य सूचना अधिकारी रह चुकी हैं। निजी क्षेत्र में भी उनके पास साइबर सुरक्षा का करीब दो दशक का अनुभव है। वह साइबर सुरक्षा से संबंधित वैश्विक कंपनियों यूनिलीवर, एस्टी लॉडर, बार्कलेज और सीमेंस में शीर्ष अधिकारी रही हैं। एक्सिओस की रिपोर्ट में इस बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) टीम में बदलाव कर रहे हैं। इसी क्रम में, गुरुवार को व्हाइट हाउस ने कर्स्टन ए. डेविस को नया राष्ट्रीय साइबर नियुक्त किया। उनके पास अपने पूर्ववर्ती शॉन केर्नक्रॉस की तुलना में इस क्षेत्र का अधिक अनुभव है। व्हाइट हाउस के दो अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के नए चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने इस बदलाव की जरूरत जोर दिया। इसके बाद उन्होंने केर्नक्रॉस को हटा दिया। ऑफिस ऑफ द नेशनल साइबर डायरेक्टर पूरी संघीय सरकार (फेडरल गवर्नमेंट) में साइबर सुरक्षा नीति और रणनीति के बीच समन्वय का काम करता है। इस पद के लिए सीनेट की मंजूरी जरूरी है। इससे पहले रक्षा विभाग की चीफ इनफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में डेविस को सीनेट से मंजूरी मिल चुकी है। डेविस पेंटागन में रक्षा सचिव (डिफेंस सेक्रेटरी) पीट हेगसेथ की मुख्य सलाहकार रह चुकी हैं। वह उन्हें 'सूचना प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों' पर सलाह देती थीं। डेविस इंस्टीट्यूट फॉर साइबर की संस्थापक हैं। यह गैर लाभकारी संगठन है और डिजिटल दुनिया में नागरिकों की सुरक्षा के लिए समर्पित है।

जनकपुरधाम में विवाह पंचमी महोत्सव की तैयारियां तेज, व्यवस्थाओं के लिए समितियों का गठन



काठमांडू। जनकपुरधाम में आगामी 9 दिसंबर से शुरू होने वाले सप्ताहिक श्रीराम-जानकी विवाह पंचमी महामहोत्सव की तैयारियां तेज हैं। महोत्सव को भव्य, व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से जानकी मंदिर ने शांति-सुरक्षा, प्रचार-प्रसार, बाजार प्रबंधन, रंगभूमि मैदान एवं प्रवेश द्वार की व्यवस्था, पंडाल निर्माण, यातायात, पेयजल और बिजली प्रबंधन सहित विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग समितियां बनाई हैं। मंदिर परिसर में आयोजित सर्वपक्षीय बैठक में समितियों के गठन और उनके बीच जिम्मेदारियों के बंटवारे का निर्णय लिया गया। इस वर्ष के महोत्सव को पिछले वर्षों की तुलना में और अधिक व्यवस्थित एवं भव्य बनाने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई । बैठक जानकी मंदिर के महंत रामतपेश्वर दास वैष्णव के नेतृत्व तथा उत्तराधिकारी महंत रामरोशन दास वैष्णव के संयोजन में हुई। महंत दास ने बताया कि महोत्सव को सफल बनाने के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि महोत्सव को व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकायों, स्थानीय तहों (निकायों) और संबंधित सभी पक्षों के बीच प्रभावी समन्वय एवं सहयोग जरूरी है। विवाहपंचमी महोत्सव में शामिल होने के लिए नेपाल के विभिन्न जिलों के साथ-साथ भारत के अयोध्या सहित अन्य स्थानों से हजारों साधु-संत और श्रद्धालु जनकपुरधाम पहुंचेंगे। उनके स्वागत, आवास, सुरक्षा और आवागमन को सहज बनाने के विषय को बैठक में प्राथमिकता दी गई। बैठक में धार्मिक संघ-संस्थाओं, नागरिक समाज, जनप्रतिनिधियों, सुरक्षा निकायों, मीडिया क्षेत्र तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयों के प्रतिनिधियों की भागीदारी रही।

नेपाल के पूर्व मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

काठमांडू। नेपाल के पूर्व मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल के खिलाफ मलेशिया जाने वाले नेपाली प्रवासी श्रमिकों से कथित ठगी के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। यह गिरफ्तारी वारंट नेपाल पुलिस के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीआईबी) की जांच रिपोर्ट के आधार पर काठमांडू जिला अदालत ने जारी किया है। सीआईबी प्रमुख एवं अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (एआईजी) उमा चतुर्वेदी ने इसकी पुष्टि की है। इस मामले में बुधवार को सीआईबी ने दो पूर्व मंत्रियों सहित सरकार के छह वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें पूर्व श्रम मंत्री शेरबहादुर कुँवर और रामेश्वर राय यादव, तत्कालीन सचिव विनोद केसी, सहसचिव राजीव पोखरेल और उमेश ढुंगाना तथा उपसचिव निर्मला गुरुङ शामिल हैं। इससे पहले इसी मामले में कारोबारी कैलाश खड़का सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया गया है कि गिरफ्तारी वारंट जारी होने से एक दिन पहले गुरुवार सुबह अर्याल दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं। एआईजी चतुर्वेदी ने बताया कि गिरफ्तारी वारंट से पहले मंत्रालय से कुछ कागजात मांगे गए थे। हो सकता है मंत्रालय के किसी व्यक्ति ने उनको इस बात की सूचना दी हो। उन्होंने कहा कि हवाईअड्डा इमिग्रेशन से पता चला है कि वो दिल्ली के विमान में सवार होकर वो फरार हो गए हैं।

बांग्लादेश में विदेश राज्यमंत्री के घर के बाहर आगजनी, एनसीपी नेता के आवास पर फेंका बम

ढाका,एजेंसी। बांग्लादेश में हालात तनावपूर्ण हैं। आगजनी और बमबारी की घटनाएं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए चुनौती बनी हुई हैं। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के दिसंबर में घरवापसी की घोषणा के बाद से उनकी पार्टी अवामी लीग और सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच झड़पें शुरू होने से आम आदमी की मुसीबत बढ़ गई है। आगजनी की ताजा घटना विदेश राज्यमंत्री हुमांयू कबीर के घर के बाहर हुई है। वहीं एक नेता के घर को बम से निशाना बनाया गया। छात्र विद्रोह और शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद सरकार अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा चुकी है। प्रोथोम अलो, ढाका ट्रिब्यून और द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार आज तड़के सिलहट शहर के दरियापारा इलाके में विदेश राज्यमंत्री हुमायूं कबीर के घर की ओर जाने वाली गली के मुख्य गेट पर कुछ लोगों ने आग लगा दी। पुलिस के अनुसार यह घटना सुबह करीब 3:30 बजे हुई। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ और न ही किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचा।

पुलिस ने बताया कि इस गली में तीन-चार घर हैं, जिनमें राज्यमंत्री का घर भी शामिल है। सुबह 3:00 से 3:30 बजे के बीच हमलावरों ने गली के मुख्य गेट के अंदर पॉलीथीन जैसी चीजों में आग लगा दी। सिलहट मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त (सीटीएसबी और मीडिया) मो. अफजल हुसैन ने कहा कि इस घटना में किसी देसी बम का इस्तेमाल नहीं किया गया था। उन्होंने कहा, 'पॉलीथीन जैसी चीजें जलाई गईं। यह कोई पेट्रोल बम नहीं था। उन्होंने बताया कि पुलिस इस घटना में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए



आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इस संबंध में सिलहट फायर सर्विस और सिविल डिफेंस कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि विभाग को गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह के बीच सिलहट में कहीं भी आग लगने की कोई सूचना नहीं मिली। सिलहट मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिप्टी कमिश्नर (मीडिया) अफजल हुसैन ने बताया कि उपद्रवियों ने कपड़ों के टुकड़ों में आग लगा दी। हालांकि, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय निवासियों और पुलिस सूत्रों के अनुसार इस घर में राज्यमंत्री के चाचा और परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं। जब राज्यमंत्री सिलहट आते हैं, तो वे यहीं ठहरते हैं। उनके शुक्रवार दोपहर बाद सिलहट पहुंचने का कार्यक्रम है। राज्यमंत्री के घर के बाहर आग लगने की खबर मिलने के बाद सिलहट विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रजाउल हसन कोयेस लुधी शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे मौके पर पहुंचे। इससे पहले नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) से संबद्ध संगठन 'जातीय स्वेच्छासेवक शक्ति' के संयोजक और भेदभाव-विरोधी छात्र आंदोलन के पूर्व समन्वयक माहिन सरकार के गांव स्थित घर पर पेट्रोल बम फेंकने की भी खबर आई। इस वजह से घर के प्रवेश द्वार पर आग लग गई। यह घटना गुरुवार रात करीब 9:30 बजे उपजिला के शेरनगर गांव में हुई। घटना के समय माहिन ढाका में थे। घर पर उनके बीमार माता-पिता मौजूद थे। माहिन सरकार ने आरोप लगाया है कि अवामी लीग के सदस्य लंबे समय से उनके घर में आग लगाने की धमकी दे रहे थे। पुलिस आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश में 7 से 18 नवंबर के बीच 78 जगहों पर देसी बम धमाके हुए, जबकि इन 12 दिनों में 74 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इन घटनाओं के संबंध में पूरे देश में कुल 38 मामले दर्ज किए गए हैं।

नेपाल में महंगाई दर बढ़कर 6.37 प्रतिशत पहुंची, विदेशी मुद्रा भंडार में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि

काठमांडू। नेपाल में महंगाई दर में पिछले एक साल के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नेपाल राष्ट्र बैंक के अनुसार, अक्टूबर 2026 के अंत तक सालाना उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (महंगाई दर) बढ़कर 6.37 प्रतिशत पहुंच गई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 1.47 प्रतिशत थी।

समीक्षा अवधि में खाद्य एवं पेय पदार्थों की महंगाई दर 8.04 प्रतिशत और गैर-खाद्य एवं सेवा क्षेत्र की महंगाई दर 5.46 प्रतिशत रही। पिछले वर्ष इसी अवधि में खाद्य एवं पेय पदार्थों के मूल्य सूचकांक में 2.54 प्रतिशत की गिरावट आई थी, जबकि गैर-खाद्य एवं सेवा क्षेत्र के मूल्य सूचकांक में 3.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। नेपाल राष्ट्र बैंक की ओर से सार्वजनिक की गई चालू आर्थिक वर्ष 2026/27 के पहले तीन महीनों (अगस्त से अक्टूबर तक) की समसामयिक व्यापक आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति संबंधी रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के तीसरे महीने में औसत महंगाई दर 6.22 प्रतिशत रही। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 1.67 प्रतिशत थी। रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल का कुल विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई 2026 के 3,897.67 अरब रुपये से 6.8 प्रतिशत बढ़कर अक्टूबर 2026 में 4,161.14 अरब रुपये पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर में विदेशी मुद्रा भंडार 8.2 प्रतिशत बढ़कर 27.39 अरब डॉलर हो गया। मध्य जुलाई 2026 में यह 25.31 अरब डॉलर था। कुल विदेशी मुद्रा भंडार में नेपाल राष्ट्र बैंक के पास मौजूद भंडार 6.4 प्रतिशत बढ़कर 3,695.24 अरब रुपये पहुंच गया, जबकि मध्य जुलाई में यह 3,473.19 अरब रुपये था।

इसी तरह नेपाल राष्ट्र बैंक को छोड़कर बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के पास मौजूद विदेशी मुद्रा भंडार 9.8 प्रतिशत बढ़कर 465.9 अरब रुपये हो गया। जुलाई में यह 424.48 अरब रुपये था। अक्टूबर 2026 तक कुल विदेशी मुद्रा भंडार में भारतीय मुद्रा की हिस्सेदारी 21 प्रतिशत रही। समीक्षा अवधि में नेपाल का निर्यात 57 प्रतिशत बढ़ा, जबकि आयात में 38.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026/27 की समीक्षा अवधि में सरकार का कुल खर्च 396.27 अरब रुपये रहा। इसमें चालू खर्च 291.66 अरब रुपये, पूंजीगत खर्च 28.42 अरब रुपये और वित्तीय प्रबंधन खर्च 76.19 अरब रुपये रहा। इसी अवधि में प्रांतीय और स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित की जाने वाली राशि सहित सरकार का कुल राजस्व संग्रह 298.61 अरब रुपये रहा। इसमें कर राजस्व 279.35 अरब रुपये और गैर-कर राजस्व 19.27 अरब रुपये शामिल हैं।

नेपाल में डायलिसिस फ्लूड की कमी से 400 से अधिक किडनी मरीजों का इलाज प्रभावित

काठमांडू। नेपाल में पेरिटोनियल डायलिसिस (पीडी) कराने वाले 400 से अधिक किडनी मरीज जरूरी डायलिसिस फ्लूड की कमी के कारण अपना इलाज जारी रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पेट में कैथेटर डालकर घर पर ही की जाने वाली इस उपचार पद्धति के लिए आवश्यक फ्लूड की नियमित आपूर्ति नहीं होने से मरीजों का इलाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

नेपाल में इस फ्लूड की आपूर्ति करने वाली एकमात्र कंपनी से पिछले तीन महीनों से मरीजों को नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में फ्लूड नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण जीवन बचाने के लिए पीडी पर निर्भर मरीजों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को काठमांडू के कालीमाटी स्थित फ्लूड वितरण केंद्र पर 20 से अधिक किडनी मरीज जरूरी फ्लूड लेने के लिए पहुंचे। इन्हीं मरीजों में 45 वर्षीय किरण थापा भी शामिल थीं। नियमित डायलिसिस नहीं हो पाने के कारण उनके शरीर में सूजन आ गई है। उन्हें सांस लेने और बोलने में भी परेशानी हो रही है। सानेपा में रहने वाली थापा पिछले 12 वर्षों से किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं। शुरुआत में अस्पतालों में उनकी हीमोडायलिसिस की जाती थी, लेकिन हाथ में फिस्टुला (डायलिसिस के लिए रक्त वाहिका तक पहुंच बनाने की प्रक्रिया) खराब होने और डॉक्टरों को दूसरी उपयुक्त नस नहीं मिलने के कारण उन्हें पेरिटोनियल डायलिसिस शुरू करना पड़ा। पीडी के जरिए उन्हें बार-बार अस्पताल जाने के बजाय घर पर ही इलाज कराने की सुविधा मिली। इस प्रक्रिया में पेट में लगाए गए कैथेटर के माध्यम से विशेष फ्लूड डाला जाता है, जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त तरल पदार्थ बाहर निकालने में मदद करता है। लेकिन अब फ्लूड की कमी ने उनका इलाज मुश्किल बना दिया है। थापा ने बताया कि उनके पैरों में सूजन आ गई है और सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा, 'मेरे पैर सूज गए हैं। रात में जब मैं लेटती हूं तो ऐसा लगता है कि तरल पदार्थ मुंह तक पहुंच रहा है। मुझे सांस लेने और यहां तक कि बोलने में भी कठिनाई होती है। थापा को दिन में चार बार डायलिसिस की जरूरत होती है, लेकिन पर्याप्त फ्लूड नहीं मिलने के कारण उन्हें दो से तीन दिनों तक बिना डायलिसिस के रहना पड़ा। उन्होंने भावुक होते हुए बताया, 'पिछले तीन महीनों से मुझे नियमित रूप से फ्लूड मिलने में परेशानी हो रही है। मैं रोजाना यहां आती हूं और एक-दो बैग फ्लूड से किसी तरह काम चलाती हूं।'

काठमांडू में सार्वजनिक शौचालयों को अनिवार्य बुनियादी सेवा के रूप में संचालित करने का निर्देश

काठमांडू,एजेंसी। काठमांडू महानगरपालिका की कार्यवाहक मेयर सुनीता डंगोल ने सार्वजनिक शौचालयों का संचालन आवश्यक, बुनियादी और अनिवार्य सेवा के रूप में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। शहर में सार्वजनिक शौचालयों की मौजूदा स्थिति और उनके उचित संचालन की जरूरतों को लेकर शहरी योजना आयोग की अध्ययन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कार्यवाहक मेयर डंगोल ने शौचालयों को स्वच्छ, सुरक्षित, व्यवस्थित, समावेशी और सभी नागरिकों की पहुंच में लाने वाले कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।

शहरी योजना आयोग ने हाल ही में महानगर क्षेत्र के 169 सार्वजनिक शौचालयों का अध्ययन किया था। इसमें उनकी मौजूदा स्थिति, संचालन प्रणाली, भौतिक संरचना, साफ-सफाई, पानी की उपलब्धता और दिव्यांगों के लिए पहुंच जैसी सुविधाओं का मूल्यांकन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि इन शौचालयों में सुधार की आवश्यकता है। अध्ययन रिपोर्ट में नए शौचालयों की संख्या बढ़ाने के बजाय मौजूदा शौचालयों के बेहतर प्रबंधन, गुणवत्ता और उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं पर ध्यान देने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, पहले से संचालित शौचालयों की सुविधाओं को नियमित रखरखाव, स्तरोन्नति और पुनर्निर्माण के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है। कार्यवाहक मेयर डंगोल ने महानगरपालिका के अनुरोध पर पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से अपने यहां संचालित शौचालयों की साफ-सफाई में सुधार करने और उन्हें अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के



प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, 'हर सार्वजनिक शौचालय को महिलाओं, बच्चों के अनुकूल और सभी की पहुंच में होना चाहिए। आइए, इस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ पूरा करें। अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आयोग के सदस्य दामोदर गिरी ने बताया कि महानगर क्षेत्र के कुल 169 सार्वजनिक शौचालयों में से 113 नियमित रूप से संचालित हैं। नौ आंशिक रूप से संचालित हैं, 10 निर्माणाधीन हैं, 14 बंद या उपयोग में नहीं हैं और दो पूरी तरह अनुपयोगी हैं। वहीं, 21 शौचालयों की संचालन स्थिति स्पष्ट नहीं है। अध्ययन में नए सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए स्थान चयन को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं। इसके अनुसार, केवल जमीन की उपलब्धता को आधार बनाने के बजाय पैदल यात्रियों और वाहनों की पहुंच, पानी की उपलब्धता, जल निकासी व्यवस्था, उपयोगकर्ताओं की मांग और संचालन की व्यवहार्यता को भी ध्यान में रखना जरूरी है। साथ ही जमीन के स्वामित्व और निर्माण संबंधी पहलुओं का मूल्यांकन कर उपयुक्त स्थानों की पहचान करने की जरूरत बताई गई है। काठमांडू महानगरपालिका ने अध्ययन से प्राप्त सुझावों को तत्काल, मध्यम अवधि और दीर्घकालीन कार्यों में वर्गीकृत कर कार्ययोजना के माध्यम से सुधार प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने इस वर्ष 19 अगस्त से अध्ययन शुरू किया था। इसके तहत मौजूदा नीतियों, कानूनों और संस्थागत व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। वार्ड स्तर पर उपलब्ध एकीकृत रिकॉर्ड का सत्यापन करने के साथ ही सार्वजनिक शौचालयों का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया।

बांग्लादेश में अवामी लीग के पूर्व सांसद अताउल हक डोलन गिरफ्तार, अभिनेता टोमल महबूब हिरासत में

ढाका,एजेंसी। बांग्लादेश में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी के नेताओं और समर्थकों की धरपकड़ तेज हो गई है। हसीना के दिसंबर में स्वदेश लौटने की घोषणा पर सरकार के नकारात्मक रुख से देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। गोपालगंज से लेकर ढाका तक तनाव है। बिगड़े हालात के बीच गुरुवार देररात ढाका में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने सतखीरा-4 से अवामी लीग के पूर्व सांसद एसएम अताउल हक डोलन को गिरफ्तार कर लिया। उधर, अभिनेता टोमल महबूब को देररात हिरासत में ले लिया। द डेली स्टार और ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, स्पेशल रिस्पॉन्स बटालियन (एसआरबी) ने राजधानी के बारीधारा इलाके से डोलन को गिरफ्तार किया। एसआरबी के लीगल एंड मीडिया विंग के निदेशक, विंग कमांडर एमजेडएम इंतखाब चौधरी ने बताया कि हमारी टीम ने कार्रवाई करते हुए रात करीब 11:20 बजे उन्हें गिरफ्तार किया। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच (डीबी) को सौंपा जाएगा। एसआरबी ने यह नहीं बताया कि डोलन को किस मामले में गिरफ्तार किया गया है।

इस बीच, ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने राजधानी से अभिनेता टोमल महबूब को हिरासत में लिया। डीबी प्रमुख शफीकुल इस्लाम ने उनकी हिरासत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अभिनेता पर भड़काऊ गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। अभिनेता टोमल महबूब को



फिलहाल उनके मिंटू रोड स्थित कार्यालय में रखा गया है। उन्हें डोलन की गिरफ्तारी से कुछ समय पहले राजधानी के अजीमपुर इलाके में ईरानी मठ के पास से हिरासत में लिया गया। शफीकुल इस्लाम ने उन्हें हिरासत में लेने का कारण बताने से इनकार कर दिया। इस समय देश के 64 जिलों में से कम से कम 28 अशांत हैं।

शेख हसीना ने अपनी मौत की सजा सुनाए जाने की पहली बरसी के आसपास दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का इरादा जताया है। उन्होंने नए पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए आवेदन भी किया, जिसे वर्तमान सरकार ने खारिज कर दिया है। सड़कों पर उतरे अवामी लीग के कार्यकर्ताओं और सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के समर्थकों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। उपद्रवियों ने चटगांव में पूर्व अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस के पैतृक आवास में भी आगजनी की है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार ने अकेले राजधानी ढाका में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के 3,000 जवानों (96 प्लाटून) को तैनात किया है। अवामी लीग के दर्जनों समर्थकों को गिरफ्तार किया गयाहै। बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता के साथ गंभीर आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है। देश में महंगाई दर 8 फीसद से ऊपर बनी हुई है। ऊर्जा संकट गहरा गया है। विश्व बैंक ने देश की विकास दर के अनुमान को घटाकर 3.4 प्रतिशत कर दिया है।

बालेन्द्र को निजी क्षेत्र का सुझाव, नेपाल-भारत व्यापार में गैर-टैरिफ बाधाएं और सीमा संबंधी अड़चनें दूर करने का हो प्रयास

काठमांडू। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ने नेपाल और भारत के बीच व्यापार में गैर-टैरिफ बाधाओं, नीतिगत अनिश्चितता और सीमा नाकों पर होने वाली प्रक्रियागत जटिलताओं को दूर करने के लिए सरकार से पहल करने का आग्रह किया है। महासंघ ने प्रधानमंत्री की आगामी भारत यात्रा के दौरान इन मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाने का सुझाव दिया है। महासंघ के अध्यक्ष अंजन श्रेष्ठ ने कहा कि नेपाली वस्तुओं के निर्यात में भारत की ओर से अलग-अलग नामों पर गैर-टैरिफ बाधाएं खड़ी की जा रही हैं। इन बाधाओं को समाप्त करने के लिए उच्चस्तरीय पहल जरूरी है। महासंघ का कहना है कि भारतीय बाजार में नेपाली उत्पादों को सहज पहुंच नहीं मिलने से नेपाली उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हो रही है और उत्पादन लागत भी बढ़ रही है।

महासंघ ने नेपाली जूट उत्पादों पर भारत की ओर से लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क को हटाने की मांग की है। महासंघ के अनुसार, 5 जनवरी 2016 से लागू इस शुल्क के कारण नेपाली जूट उद्योग के निर्यात और किसानों के रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की खरीद प्रक्रिया में नेपाली जूट उद्योग पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का भी आग्रह किया गया है। महासंघ ने बताया कि स्टील पर सेफगार्ड शुल्क और स्टील आयात निगरानी प्रणाली, प्लाइवुड तथा दालचीनी पर बिना पूर्व सूचना लागू किए गए नियमों से नेपाली उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। इसी तरह, बड़ी इलायची, चाय और अदरक सहित कृषि उत्पादों के निर्यात में सामने आ रही गैर-टैरिफ बाधाओं को भी दूर करने की मांग की गई है।

व्यापार को आसान बनाने के लिए महासंघ ने नेपाल के गुणवत्ता प्रमाणन चिह्न को भारत के गुणवत्ता प्रमाणपत्र के समान मान्यता देने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही दोनों देशों के सीमा नाकों पर प्रयोगशालाएं और क्वारंटाइन केंद्र स्थापित करने तथा नेपाल में किए गए उत्पाद परीक्षण को भारत की ओर से मान्यता देने की मांग की गई है। महासंघ ने सीमा नाकों के संचालन का समय बढ़ाने, खाली ट्रकों पर लगने वाला शुल्क हटाने, निर्यात सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी को समाप्त करने और नेपाली वाहनों को भारतीय टोल प्लाजा पर फास्टैग सुविधा उपलब्ध कराने का भी सुझाव दिया है। पारवहन सुविधा के तहत महासंघ ने कोलकाता, हल्दिया और विशाखापत्तनम के अलावा गुजरात के मुंद्रा, ओडिशा के धामरा और मुंबई के बंदरगाहों के इस्तेमाल की अनुमति देने का सुझाव दिया है। इसके अलावा, रक्सौल-वीरगंज रेल लिंक का विद्युतीकरण करने, अन्य सीमा नाकों तक रेल संपर्क का विस्तार करने और सड़क मार्ग से होने वाले माल परिवहन में इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग प्रणाली लागू करने की मांग की गई है।

एक नजर

लोस अध्यक्ष व अन्य ने 'देव उठानी एकादशी' पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली,एजेंसी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा मंत्र राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने शुक्रवार को कार्तिक शुक्ल एकादशी के पावन पर्व 'देव उठानी एकादशी' पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। बिरला ने एक्स पर लिखा, 'भारतीय साहित्य और प्राचीन धार्मिक परंपराओं में, देव उठानी एकादशी का विशेष आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह वह पवित्र अवसर माना जाता है जब भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग-निद्रा से जागते हैं। इसी दिन से 'चातुर्मास' का समापन होता है और विवाह सहित कई मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। 'तुलसी विवाह' की परंपरा इस पर्व को और भी विशेष बना देती है। यह उत्सव हमारी सनातन जीवन-पद्धति में प्रकृति, उपासना, पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक कल्याण के सुंदर सामंजस्य को दर्शाता है। देव उठानी एकादशी का यह पावन अवसर हमें नई ऊर्जा, शुभ संकल्पों और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से प्रत्येक परिवार में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो। हमारी सनातन परंपराओं की यह अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर समाज में सद्भावना, सामंजस्य और जन-कल्याण की भावना को और सुदृढ़ करे; और हमारा राष्ट्र निरंतर प्रगति, समृद्धि तथा सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर रहे। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय संस्कृति और आस्था में देव उठानी एकादशी का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, और हर परिवार के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि आए।' केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा से सभी का जीवन सुख, शांति एवं समृद्धि से भर जाए, यही उनकी प्रार्थना है।

केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह के अवसर पर संसार के पालनहार भगवान विष्णु के चरणों में साष्टांग नमन करते हैं। केन्द्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी की कृपा से आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य आए। सभी शुभ कार्यों की यह मंगलमय शुरुआत आपके लिए सौभाग्य लेकर आए।

शादी का झांसा देकर 14 महिलाओं के शोषण के आरोपित मोहम्मद माजिन का यूएई से प्रत्यर्पण

नई दिल्ली। शादी का झांसा देकर महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करने का आरोपित मोहम्मद माजिन को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत लाया गया है। महाराष्ट्र पुलिस के वांछित आरोपित को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र पुलिस के समन्वय से शुक्रवार को भारत वापस लाने की कार्रवाई पूरी की। आरोपित कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा, जहां उसे महाराष्ट्र पुलिस की टीम को सौंप दिया गया। सीबीआई के अनुसार, मोहम्मद माजिन महाराष्ट्र पुलिस में दर्ज एक मामले में वांछित था। उस पर एक महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने और उसका शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक शोषण करने का आरोप है। आरोप है कि मोहम्मद माजिन ने संबंधित महिला से 18 लाख रुपये भी ठगे थे। इस मामले में सक्षम अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपित ने शादी का झांसा देकर 13 अन्य महिलाओं का भी इसी तरह शोषण किया। उसने उनसे पैसे लिए और उनके साथ अंतरंग संबंधों के वीडियो भी रिकॉर्ड किए। इसके बाद वह विदेश भाग गया। महाराष्ट्र पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई की ओर से इंटरपोल के माध्यम से आरोपित के खिलाफ रेड नोटिस जारी कराया गया था। इसके बाद उसकी लोकेशन का पता लगाकर यूएई के अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार किया। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद यूएई के अधिकारियों ने उसे भारत भेजने की अनुमति दी। महाराष्ट्र पुलिस की एक टीम आरोपित को लेने यूएई पहुंची थी। वहां उसे भारतीय टीम को सौंपा गया। इसके बाद टीम शुक्रवार को आरोपित के साथ कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची। सीबीआई ने वर्ष 2019 से अब तक इंटरपोल के माध्यम से 300 से अधिक वांछित अपराधियों का भारत में वापस प्रत्यर्पण कराया है। इनमें वर्ष 2026 में अब तक 74 भगोड़े शामिल हैं।

गुरु नानक देव जी का 557वां प्रकाश पर्व 22 को, निकाली गई अंतिम प्रभात फेरी

रांची,एजेंसी। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा, कृष्णा नगर कॉलोनी की ओर से अंतिम दिन शुक्रवार को प्रभात फेरी निकाली गई। इसी के साथ ही शहर की तमाम प्रभातफेरियों का समापन हो गया। तड़के सुबह प्रभात फेरी गुरुद्वारा साहिब के पार्किंग गेट से निकल कर मेट्रो गली, रातू रोड होते हुए नागा बाबा खटाल चौक पहुंची जहां इसका मिलन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, मेन रोड एवं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, पिस्का मोड़ की प्रभातफेरियों से हुआ। वहां से तीनों प्रभातफेरियां सम्मिलित होकर महावीर चौक, कुंजलाल स्ट्रीट, शास्त्री मार्केट, डेली मार्किट होते हुए मेन रोड गुरुद्वारा साहिब पहुंच कर अरदास के साथ समाप्त हो गई। इसी के साथ गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में पिछले 13 दिनों से निकाली जा रही शहर की तमाम प्रभावफेरियों का समापन हो गया। प्रभात फेरी में शामिल श्रद्धालुओं ने 'सतगुरू नानक परगटया मिट्टी धुंध जग चानन होआ..और कल तारण गुरुनानक आया...एवं देह शिवा वर मोहे इहे शुभ करमन ते कबहुं ना टरौं... जैसे अनेक शबद गायन कर पूरे शहर को नानकमय कर दिया। फेरी का तारा हैंडलूम, एसके सूट एंड साड़ीज, कुंजलाल स्ट्रीट दुकानदार एसोसिएशन, शास्त्री मार्केट एसोसिएशन और नटराज होटल डेली मार्केट ने पुष्प वर्षा एवं चाय तथा मिष्टान्न प्रसाद का वितरण कर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर गुरु सिंह सभा की ओर से गुरु का अटूट



लंगर भी चलाया गया। सरदार छोटू सिंह ने निशान साहिब उठाकर फेरी की अगुवाई की और मनीष मिढा ने श्रद्धालुओं के घरों एवं प्रतिष्ठानों के सामने अरदास की। गुरुद्वारा श्री गुरुनानक सत्संग सभा ने श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व 22 नवंबर को कृष्णा नगर कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा मैदान में मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में सुबह 10 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक विशेष दीवान सजाया जाएगा जिसमें सिख पंथ के महान कीर्तनी जत्था भाई गुरमनप्रीत सिंह दिल्ली वाले विशेष रूप से शिरकत करेंगे। राज्यपाल संतोष गंगवार समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ विशिष्ट अतिथि होंगे। इसके अलावा झारखंड सरकार में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रांची के विधायक सीपी सिंह सहित अन्य गन्यमान्य शामिल होंगे। विशेष दीवान की समाप्ति के बाद दोपहर तीन बजे गुरुद्वारा मैदान,कृष्णा नगर कॉलोनी से भव्य नगर कीर्तन निकाला जाएगा जो रातु रोड,प्यादा टोली,गांधी चौक,शहीद चौक,अल्बर्ट एक्का चौक,डेली मार्केट,चर्च कॉम्प्लेक्स,लाला लाजपत राय चौक से होते हुए पीपी कंपाउंड स्थित गुरुनानक स्कूल परिसर पहुंचकर रात में बजे समाप्त होगा। गुरुनानक सत्संग सभा के अध्यक्ष अर्जुन देव मिड्ढा ने राज्य के सभी सिख धर्मावलंबियों से प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सजाए जा रहे सभी दीवानों में हाजिरी लगाने का आग्रह किया है।

सूरत में 45 मिनट में 5 सीरियल लूट करने वाले दोनों बदमाश 24 घंटे में पकड़े गये

सूरत,एजेंसी। शहर में 19 नवंबर की सुबह मात्र 45 मिनट में 5 सीरियल लूट और चाकूबाजी की वारदातों को अंजाम देकर दहशत फैलाने वाले दोनों आरोपितों को सूरत पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दो अलग-अलग 'हाफ एनकाउंटर' में काबू कर लिया है। क्राइम ब्रांच की कस्टडी से भागने और पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीनने की कोशिश के दौरान दूसरे आरोपित लक्ष्मणकुमार उर्फ गुड्डू दिलीप उर्फ इंद्र यादव के पैर में गोली लगी है।

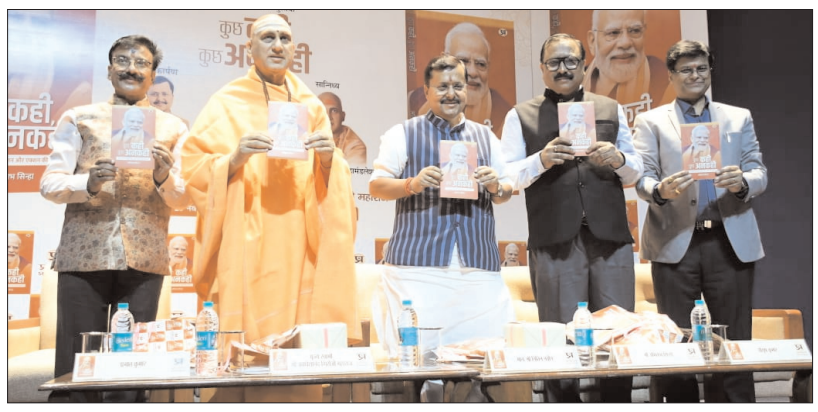
क्राइम ब्रांच के डीसीपी भावेश रोजिया के अनुसार वराछा, महिधरपुरा और कतारगाम थाना क्षेत्रों में 45 मिनट के भीतर 3 लूट और 2 गंभीर चोट (ग्रीवियस हार्ट) समेत कुल 5 मामले दर्ज हुए थे। पुलिस के मुताबिक पहले आरोपित परवेज मुर्शरफ अंसारी को लिंबायत पुलिस ने देररात करीब 3 बजे नीलगिरी ग्राउंड के पास नाइट पेट्रोलिंग के दौरान पकड़ा था। पीछा करने के दौरान आरोपित ने चाकू से पुलिसकर्मी अनिलकुमार अमरसिंह की कमर पर वार किया था, जिसके बाद चेतावनी के बावजूद न मानने पर पुलिस ने पहले हवा में एक राउंड फायरिंग की और फिर आत्मरक्षा में उसके बाएं पैर में गोली मारी। पूछताछ में मूल रूप से झारखंड निवासी और हाल लिंबायत के ममता टॉकीज के पास रहने वाले परवेज ने अपने साथी लक्ष्मण उर्फ गुड्डू के साथ मिलकर लूट की वारदातें कबूल की थीं। गजेरा सर्कल के पास से लूटे गए 6 मोबाइल समेत कुल ?66,000 का मुद्देमाल जब्त किया गया था। घायल परवेज को सूरत की नई सिविल अस्पताल और घायल कॉन्स्टेबल अनिलकुमार को लिंबायत की गैलेक्सी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लिंबायत पुलिस का पिछले 6 महीनों में यह दूसरा देर रात हाफ एनकाउंटर है। इससे पहले 11 मई 2026 को भी हत्या के एक आरोपित पर फायरिंग कर उसे पकड़ा गया था। वहीं, दूसरे आरोपित लक्ष्मणकुमार उर्फ गुड्डू को क्राइम ब्रांच की टीम ने लिंबायत की ममता चौकी के पास से गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के समय उसकी टी-शर्ट पर बंदूक और 'वॉन्टेड' का चिह्न छपा था और कुछ ही घंटों बाद उसी तरह की पिस्तौल से चली पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। पूछताछ के बाद मेडिकल जांच के लिए चौक बाजार स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय से नई सिविल अस्पताल ले जाते समय स्वामीनारायण मंदिर के पास पुलिस वाहन के अगले टायर में हवा कम होने पर गाड़ी रोकी गई। ड्राइवर और दो कॉन्स्टेबल टायर देखने नीचे उतरे, जबकि गाड़ी में पीएसआई और बिना हथकड़ी का आरोपित पास बैठे थे। आरोप है कि इसी दौरान लक्ष्मण ने पास बैठे पीएसआई की रिवॉल्वर खींचने और हमला करने का प्रयास किया।

एनसीडीईएक्स पर बिनौला खली और अरंडी में उछाल, धनिया और मसालों पर रहा दबाव

नई दिल्ली,एजेंसी। घरेलू कृषि कमोडिटी बाजार (नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज-एनसीडीईएक्स) में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन आज शुरुआती कारोबार के दौरान मिला-जुला रुख नजर आ रहा है। देश की प्रमुख कृषि उपज मंडियों से मिल रही आवक की स्थिति और निर्यात मांग के संकेतों के बीच आज सुबह खली और तिलहन फसलों में अच्छी खरीदारी दर्ज की जा रही है। इसके विपरीत, मसाला और ग्वार कॉम्प्लेक्स में ऊपरी स्तर पर हल्की मुनाफावसूली और सीमित दायरे का कारोबार दिख रहा है।

बिनौला खली और तिलहन फसलों की बात करें तो आज सुबह नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पर बिनौला खली यानी कॉटन सीड ऑयल केक के भाव में जोरदार तेजी के साथ शुरुआत हुई है। दिसंबर डिलीवरी वाला बिनौला खली कॉन्ट्रैक्ट 1.24 प्रतिशत की मजबूती के साथ 3,992 से 3,994 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर कारोबार करता देखा गया। इसी तरह जनवरी और फरवरी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी दो प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। पशु चारे की मांग बढ़ने और कपास की आवक सीमित रहने से इन कीमतों को सीधा सहारा मिल रहा है। अरंडी के बीज यानी कैस्टर सीड के बाजार में भी आज सुबह खरीदारों का दबदबा कायम है। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट वाला कैस्टर सीड वायदा 1.28 प्रतिशत की बढ़त के साथ 8,380 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर कामकाज कर रहा है, जबकि जनवरी कॉन्ट्रैक्ट भी 1.01 प्रतिशत मजबूत होकर 8,420 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर पहुंच गया है। गुजरात की डीसा और कडी जैसी प्रमुख हाजिर मंडियों में अरंडी के भाव 8,135 से 8,195 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास मजबूत स्तर पर बने हुए हैं, जिसका सकारात्मक असर वायदा बाजार पर दिख रहा है। मसाला और ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो आज सुबह इन जिंसों में सतर्कता के साथ सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। जीरा वायदा में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 28,430 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर के आसपास स्थिर रुख के साथ कामकाज कर रहा है, जबकि उंझा मंडी में इसका हाजिर भाव 28,455 रुपये प्रति क्विंटल के करीब बना हुआ है। धनिया वायदा में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 0.95 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 14,450 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि कोटा मंडी में इसका हाजिर भाव 16,719 रुपये के आसपास दर्ज किया गया है। इसी तरह ग्वार कॉम्प्लेक्स में भी आज सुबह मिला-जुला रुख नजर आ रहा है। जोधपुर मंडी में ग्वार गम का हाजिर भाव 16,561 रुपये और ग्वार सीड का हाजिर भाव 8,301 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर के आसपास बना हुआ है। वायदा बाजार में जनवरी कॉन्ट्रैक्ट वाला ग्वार सीड 8,545 रुपये प्रति क्विंटल के दायरे में सीमित उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार कर रहा है। हल्दी के बाजार में भी उत्पादक केंद्रों से मिल रहे संकेतों के बीच सीमित दायरे में खरीदारी और मुनाफावसूली का दौर जारी है।

पुस्तक 'कुछ कही, कुछ अनकही' का विमोचन, भाजपा अध्यक्ष ने बताये प्रधानमंत्री की कार्यशैली के पांच मंत्र



नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नबीन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर लिखी एक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर कहा कि उनपर लिखी हर पुस्तक में उनकी कार्यशैली के पांच प्रमुख मंत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यह हैं- लीक से हटकर सोचने की क्षमता, अपनी सीमाओं को चुनौती देने का संकल्प, बुनियादी जरूरतों और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना, नए मानक स्थापित करना और सबसे महत्वपूर्ण देश के प्रत्येक नागरिक को साथ लेकर चलना। ये पांचों मंत्र उनकी कार्यशैली, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र निर्माण के प्रति दृष्टिकोण को रेखांकित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर, उनकी कार्यशैली, फैसले लेने के तरीके और व्यक्तित्व के अनछुए पहलुओं को समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ सिन्हा की पुस्तक 'कुछ कही, कुछ अनकही' सामने आई है। तीन मूर्ति स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय सभागार में आयोजित एक विशेष समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम में जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज भी मौजूद रहे। पुस्तक को प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रकाशित किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री की कार्यशैली के गुणों के उदाहरण भी दिए। उन्होंने बताया कि यह पांचों गुण हमें जीएसटी और आयकर सुधार, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), स्वच्छ भारत मिशन और आयुष्मान भारत योजना, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और विकसित भारत @ 2047 के सामूहिक संकल्प में दिखते हैं।

पुस्तक के बारे में नबीन ने कहा कि पुस्तक का शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कुछ बातें कही जाती हैं, जबकि कुछ अनकही रह जाती हैं। पुस्तक पढ़ने पर पाठकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के उन पहलुओं को समझने का अवसर मिलेगा, जो सामान्य तौर पर सामने नहीं आ पाते। उन्होंने कहा कि अमिताभ सिन्हा ने अपनी पत्रकारिता की यात्रा और प्रधानमंत्री के साथ अपने जुड़ाव को इस पुस्तक के माध्यम से साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का अनुभव साझा करते हुए कहा कि अमिताभ सिन्हा के साथ साक्षात्कार देने का अवसर मिला है। उनके सवाल हमेशा साफ, सीधे और स्पष्ट होते थे। उनका व्यक्तित्व भी उनकी पत्रकारिता की तरह सहज और सरल है। नितिन नबीन ने कहा कि आज पत्रकारिता में सनसनी, नैरेटिव बनाने और ब्रेकिंग न्यूज की होड़ के बीच शांत और सरल तरीके से पत्रकारिता करने वाले लोग अपनी अलग पहचान बनाते हैं। प्रधानमंत्री की कार्यशैली का जिक्र करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी की हर विषय पर एक अलग दृष्टि है। वह छोटी से छोटी बात पर ध्यान देते हैं और जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन देने के साथ-साथ सुधार के सुझाव भी देते हैं। उनका व्यक्तित्व पार्टी के कार्यकर्ताओं और पूरे संगठन के लिए ऊर्जा, शक्ति और नई प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने पुस्तक में शामिल एक दिलचस्प प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताया कि इसमें यह भी समझाया गया है कि किसी सांसद या विधायक का कार्यालय किस तरह व्यवस्थित होना चाहिए, उनके सहयोगी कैसे होने चाहिए और कार्यालय में काम करने वाले लोगों का स्वभाव कैसा होना चाहिए। इस तरह के व्यावहारिक अनुभवों को अमिताभ सिन्हा ने अपनी कहानियों के माध्यम से पुस्तक में शामिल किया है। कार्यक्रम के दौरान नितिन नवीन ने 27 अक्टूबर 2013 को पटना में आयोजित हुंकार रैली का एक महत्वपूर्ण प्रसंग साझा किया। उन्होंने बताया कि उस रैली के दौरान कई बम विस्फोट हुए थे।

विश्व शौचालय दिवस पर जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया 'स्वच्छ शौचालय-गरिमामय भविष्य' अभियान, 10 दिसंबर तक चलेगा

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्र सरकार ने विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक और संस्थागत शौचालयों की कार्यक्षमता तथा सुगमता में सुधार के लिए 'स्वच्छ शौचालय-गरिमामय भविष्य' (एसएसजीबी) अभियान 19 नवंबर से शुरू किया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत चलने वाला यह राष्ट्रव्यापी अभियान 10 दिसंबर 2026 तक चलेगा। इसका समापन मानवाधिकार दिवस पर होगा।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की संयुक्त सचिव और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की राष्ट्रीय मिशन निदेशक ऐश्वर्या सिंह ने 19 नवंबर को अभियान और इसकी रिपोर्टिंग मॉड्यूल का ई-शुभारंभ किया। इसके माध्यम से राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अभियान के तहत हुई प्रगति की जानकारी दे सकेंगे। कार्यक्रम में विभाग के अधिकारियों ने मिशन की प्रगति की जानकारी भी दी। इसके अनुसार, करीब 89.9 फीसदी गांव ओडीएफ प्लस (मॉडल) का दर्जा हासिल कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व शौचालय दिवस 2026 की थीम 'सुरक्षित शौचालय, समान भविष्य' रखी है। यह स्वच्छता को लैंगिक समानता से जोड़ती है। इसी के अनुरूप अभियान में ग्रामीण स्वच्छता सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ महिलाओं, छात्राओं और दिव्यांगजनों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभियान के तहत गांवों में सामुदायिक



स्वच्छता परिसरों और स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा पंचायत घरों जैसे संस्थानों के शौचालयों की स्थिति का आकलन किया जाएगा। जरूरत के अनुसार उनकी मरम्मत, रखरखाव और बहाली के काम किए जाएंगे। व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की मरम्मत और रखरखाव के लिए भी परिवारों को प्रेरित किया जाएगा। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से तय लक्ष्यों के अनुसार, जहां संभव होगा, एकल गड्ढे वाले शौचालयों को दोहरे गड्ढे वाले शौचालयों में और बिना सोक पिट वाले सेप्टिक टैंक को सोक पिट युक्त सेप्टिक टैंक में बदलने की योजना भी बनाई जाएगी।

अभियान में मल कीचड़ प्रबंधन के लिए मशीनीकृत निकासी की जरूरत और व्यवस्था का आकलन, सामुदायिक तथा संस्थागत शौचालयों के रखरखाव की व्यवस्था मजबूत करने और उन्हें स्वच्छ, आकर्षक तथा उपयोग के अनुकूल बनाने पर भी जोर रहेगा। इसके तहत स्थानीय दीवार चित्रों, संकेतकों और आसपास के परिसर में सुधार को प्रोत्साहित किया जाएगा। गांवों में खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) की स्थिति को बनाए रखने के लिए व्यवहार परिवर्तन और जागरूकता गतिविधियां भी चलाई जाएंगी। इसके अलावा, गांवों और ग्राम पंचायतों में स्वच्छ सेवा आकलन की स्थिति की समीक्षा कर इसे 30 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता, साबुन से हाथ धोने, मल कीचड़ प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के अनुपालन और कचरे के चार श्रेणियों में पृथक्करण के प्रति भी जागरूकता बढ़ाई जाएगी। कार्यक्रम के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, सिक्किम और कर्नाटक की स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टीमों ने अभियान के लिए अपनी कार्ययोजनाएं साझा कीं। ऐश्वर्या सिंह ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की टीमों से स्कूल प्रबंधन समितियों और संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा स्कूलों में स्वच्छता ऑडिट कराने का आह्वान किया। उन्होंने पर्यटन स्थलों सहित अधिक सार्वजनिक आवाजाही वाले स्थानों पर स्वच्छ और क्रियाशील सामुदायिक शौचालयों की जरूरत पर भी जोर दिया। अभियान के तहत स्कूल के बच्चों को स्वच्छता और साफ-सफाई के प्रति जागरूक करने के साथ सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से विभिन्न पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित कर जनभागीदारी के माध्यम से संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने की अपील की है।

सर्राफा बाजार में गिरावट जारी, 2,570 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ सोना

नई दिल्ली,एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय बाजार से पड़ रहे दबाव की वजह से घरेलू सर्राफा बाजार में गिरावट का रुख लगातार जारी है। आज सोना और चांदी दोनों चमकीली धातुओं के भाव में शुरुआती कारोबार के दौरान जोरदार कमजोरी दर्ज की गई है। देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में सोना आज 2,350 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 2,570 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है। इसी तरह चांदी के भाव में आज भी आज शुरुआती कारोबार के दौरान कमजोरी दर्ज की गई है। यह चमकीली धातु लगातार दूसरे दिन 5,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई है।

कीमत में बदलाव होने के कारण आज देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,30,680 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,30,830 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 1,19,790 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,19,940 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में भी गिरावट आने के कारण यह चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 1,79,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर



बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,30,830 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,19,940 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,30,680 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,19,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,30,730 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,19,840 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,30,680 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,19,790 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,30,680 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,19,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,30,730 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,19,840 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,30,830 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,19,940 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,30,730 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,19,840 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। चंडीगढ़ में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,30,830 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,19,940 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)